घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 61- बुधवार 31- दिसम्बर 2025,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2023-2025

उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा...

खाई में गिरी यात्रियों की बस

7 की मौत,12 से ज्यादा घायल

नैनीताल,30 दिसम्बर 2025। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में यात्रियों को ले जा रही बस 160 फुट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में छह से सात लोगों की मौत हो गई। और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा सुबह करीब 8 बजे भीकियासेन-रामनगर रोड पर शीलापानी (विनायक इलाके) के पास हुआ, जो भीकियासेन से लगभग चार किलोमीटर आगे है। बस द्वाराहाट से भीकियासेन और बसोट होते हुए रामनगर जा रही थी, तभी बताया जा रहा है कि एक मोड़ पर ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया।

बचाव अभियान जारी

हादसे की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस टीमों के साथ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के जवान मौके पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से लगातार बचाव अभियान जारी है। हादसा स्थल मुश्किल पहाड़ी इलाके में होने के कारण बचाव और राहत कार्यों में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हादसे में शामिल बस, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर यूके07 पीए4025 है, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की है और इसे सुबह करीब 11 बजे रामनगर पहुंचना था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ड्राइवर ने शीलापानी मोड़ के पास बस से कंट्रोल खो दिया। अधिकारियों ने बताया कि ड्राइवर और कंडक्टर सुरक्षित हैं।

कई घायल यात्रियों को शुरू में भीकियासेन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत वालों को बेहतर इलाज के लिए रामनगर के राम दत्त जोशी सरकारी कंबाइंड अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि एक दर्जन से ज़्यादा घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।

मृतकों में पांच पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं

गोविंद बल्लभ मठपाल (80) और उनकी पत्नी पार्वती देवी (75), जमौली के निवासी; सूबेदार नंदन सिंह अधिकारी (65), भूपाल सिंह अधिकारी के बेटे, जमौली के निवासी; तारा देवी (50), महेश चंद्र की पत्नी, बाली (पटवारी क्षेत्र) की निवासी; गणेश (25), जो भीम बहादुर का बेटा है; और उमेश (25), जिसके पिता का नाम पता नहीं है। एक और मृत युवक की पहचान अभी भी वेरिफाई की जा रही है।

सीएम धामी ने दुःख जताया

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुःख जताया है। सीएम धामी ने कहा कि वह जिला प्रशासन के संपर्क में हैं और घायलों को ज़रूरी मदद दी जा रही है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'हमें अल्मोड़ा जिले में बिखियासैंण से रामनगर जा रही बिखियासैंण-विनायक मोटर रोड पर एक बस दुर्घटना की बेहद दुःखद खबर मिली है,जिसमें यात्रियों की जान चली गई है। यह घटना बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाली है। 'उन्होंने आगे कहा,'दुर्घटना में घायल यात्रियों को जिला प्रशासन द्वारा तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए बड़े मेडिकल सेंटरों में रेफर किया गया है। पूरे मामले पर लगातार नज़र रखी जा रही है, और मैं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के लगातार संपर्क में हूं। '

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया और पीएमओ ने एक्स पर लिखा

हादसे में लोगों की जान जाने की खबर अत्यंत दुखद है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

बंगाल की सियासत पर बोले अमित शाह

घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर होगा 2026 का चुनाव,यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला

नई दिल्ली,30 दिसम्बर 2025। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर राज्यभर में सियासी गर्माहट तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारियां भी तेज कर दी है। दूसरी ओर आरोप-प्रत्यारोप भी अपने चरम पर पहुंच गया है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कोलकाता में प्रेस वार्ता की। जहां उन्होंने राज्य की तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। घुसपैठ, भ्रष्टाचार, प्रशासन समेत कई मुद्दों को लेकर शाह ने ममता सरकार को आड़े हाथ लिया। शाह ने कहा कि ममता बनर्जी चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हमें जमीन न दिए जाने के कारण हम बांग्लादेश सीमा की बाड़बंदी पूरी नहीं कर पाए हैं। साल 2026 में बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर ही होगा 2026 का पश्चिम बंगाल चुनाव।

बंगाल में आम नागरिकों में चिंता का माहौल : शाह

शाह ने आगे कहा कि बंगाल के लिए आज से अप्रैल तक का समय बेहद अहम है,क्योंकि इस दौरान राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 साल में टीएमसी सरकार के शासन में राज्य में भय,भ्रष्टाचार और गलत प्रशासन फैला है,जिसके कारण बंगाल में आम नागरिकों में चिंता का माहौल बन गया है। शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण बंगाल का विकास रुक गया है। प्रधानमंत्री मोदी की जनकल्याण योजनाएं यहां टोल सिंडिकेट की भेंट चढ़ गई हैं। पिछले 14 वर्षों से बंगाल की पहचान डर और भ्रष्टाचार बन गई है।

क्यों हो रही घुसपैठ की समस्या,क्या बोला शाह ने?

अमित शाह ने आगे पश्चिम बंगाल सरकार पर बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही, जिसकी वजह से घुसपैठ की समस्या बनी हुई है। अमित शाह ने सवाल किया कि त्रिपुरा, असम,राजस्थान,पंजाब,कश्मीर और गुजरात की सीमाओं पर घुसपैठ क्यों रुक गई,लेकिन पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि बंगाल में राज्य सरकार की जानकारी में घुसपैठ हो रही है और इसका मकसद जनसंख्या में बदलाव कर वोट बैंक मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव घुसपैठ रोकने और घुसपैठियों को बाहर निकालने इन्हीं मुद्दों पर लड़े जाएंगे। अमित शाह ने साफ कहा कि बंगाल सीमा से हो रही घुसपैठ देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

अमित शाह का दावा- 2026 में पश्चिम बंगाल में भाजपा बनाएगी सरकार

शाह ने आगे इस बात पर जोर दिया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में दो-तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ा है, जो साफ तौर पर चुनावी नतीजों में दिखता है। अमित शाह ने आंकड़े गिनाते हुए कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा को 17% वोट और तीन सीटें मिलीं, 2016 विधानसभा चुनाव में पार्टी को 10% वोट और तीन सीटें मिलीं। उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में वोट बढ़कर 41% और सीटें 18 हो गईं, 2021 विधानसभा चुनाव में भाजपा को 21% वोट और 77 सीटें मिलीं और 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी को 39% वोट और 12 सीटें मिलीं। उन्होंने कहा कि जो पार्टी 2016 में सिर्फ 3 सीटों पर थी, वह पांच साल में 77 सीटों तक पहुंच गई।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में निधन

नई दिल्ली,30 दिसम्बर 2025। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया का आज सुबह करीब 6 बजे 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे पिछले 20 दिनों से ढाका के एवरकेयर अस्पताल में वेंटिलेटर पर थीं। खालिदा जिया लंबे समय से सीने के गंभीर संक्रमण, लिवर और किडनी की बीमारी,डायबिटीज,गठिया और आंखों की समस्याओं से जूझ रही थीं। उनके परिवार और पार्टी नेताओं ने उनके निधन की पुष्टि की है। खालिदा जिया दो बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं पहली बार 1991 से 1996 और दूसरी बार 2001 से 2006 तक। वे बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान की पत्नी थीं। उनके बड़े बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान हाल ही में 25 दिसंबर को लंदन से बांग्लादेश लौटे थे, जबकि उनके छोटे बेटे अराफात रहमान का 2015 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो चुका है। गौरतलब है कि खालिदा जिया ने अपने निधन से एक दिन पहले ही, सोमवार को बोगुरा-7 सीट से चुनावी नामांकन दाखिल कराया था। उस समय उनकी हालत बेहद नाजुक थी और वे वेंटिलेटर पर थीं, इसके बावजूद बीएनपी ने उनके चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। बोगुरा-7 सीट का पार्टी के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि इसी क्षेत्र में जियाउर रहमान का आवास रहा है और खालिदा जिया यहां से तीन बार चुनाव जीत चुकी थीं। खालिदा जिया के निधन पर बीएनपी ने सात दिनों के शोक की घोषणा की है।

आईएमके आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ असम-त्रिपुरा में 11 आतंकी गिरफ्तार

गुवाहाटी,30 दिसम्बर 2025। भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने पूर्वोत्तर भारत, विशेषकर असम में सक्रिय एक कट्टरपंथी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह नेटवर्क बांग्लादेश आधारित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) से जुड़े 'इमाम महमूदर काफिला' (आईएमके) मॉड्यूल के तहत संचालित हो रहा था। असम पुलिस के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि जांच में सामने आया है कि बांग्लादेशी नागरिक उमर और खालिद को असम में गतिविधियों के समन्वय की जिम्मेदारी दी गई थी। असम मॉड्यूल का नेतृत्व बरपेटा रोड निवासी नसीम उद्दीन उर्फ तमीम कर रहा था। संगठन की गतिविधियां एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए संचालित की जा रही थीं, जिनमें 'पूर्वा आकाश' नामक समूह को मुख्य संचार और भर्ती मंच के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। खुफिया एजेंसियों के अनुसार आईएमके की स्थापना वर्ष 2018 में जेएमबी के पूर्व सदस्य ज्वेल महमूद उर्फ इमाम महमूद हबीबुल्लाह उर्फ सोहेल ने की थी। यह संगठन 'ग़ज़वतुल हिंद' की कट्टर विचारधारा का प्रचार करता है। अगस्त, 2024 में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जेएमबी, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) और अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (एक्यूआईएस) के वरिष्ठ नेताओं ने आईएमके को भारत में अपनी गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए थे। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित कर संगठन से जोड़ा गया।

पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के नाम पर डिजिटल अरेस्ट

मुंबई में बुजुर्ग महिला से 3.71 करोड़ ठगे, सूरत से एक आरोपी गिरफ्तार

मुंबई, 30 दिसम्बर 2025। मुंबई में 68 साल की एक महिला से 3.71 करोड़ की ठगी हो गई। आरोपियों ने खुद को मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन के साथ-साथ केंद्रीय एजेंसियों का कर्मचारी बताया था। इन लोगों ने नकली ऑनलाइन कोर्ट सुनवाई भी की, जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बताया था। इस मामले में साइबर पुलिस ने एक आरोपी को सूरत से पकड़ा है। आरोपी के खाते में 1.71 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। उसने यह खाता फर्जी कपड़ा कंपनी के नाम पर खुलवाया था। इसके बदले उसे 6.40 लाख रुपए कमीशन मिला।

साइबर ठगों ने 2 महीने तक धोखे में रखा

महिला मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहती है। महिला पर धोखेबाज लगातार नजर रख रहे थे। 18 अगस्त को महिला को एक कॉल आया। कॉल

करने वाले ने खुद को कोलाबा पुलिस स्टेशन का अफसर बताया। साथ ही कहा कि उसके बैंक खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हो रहा है। फिर धमकाया कि किसी को कुछ बताया तो कार्रवाई होगी। इसके बाद महिला से बैंक डिटेल्स मांगी गईं। कहा गया कि अब सीबीआई जांच करेगी। आरोपी ने महिला से उसके जीवन पर दो से तीन पेज का निबंध भी लिखवाया। फिर महिला से कहा कि उसे उसकी बेगुनाही पर यकीन हो गया है और वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसे जमानत मिल जाए।

महिला से मांगे इन्वेस्टमेंट से जुड़े दस्तावेज

एक आरोपी ने अपना नाम एसके जायसवाल बताया। उसने वीडियो कॉल पर महिला को एक व्यक्ति से मिलवाया, जिसने खुद को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस चंद्रचूड़ बताया। उसने महिला से निवेश से जुड़े दस्तावेज मांगे। महिला ने दो महीने में करीब पौने चार करोड़ रुपए खातों में ट्रांसफर कर दिए। कॉल न आने पर महिला को ठगी का अहसास हुआ। इसके बाद महिला ने वेस्ट रीजन साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। फिर मामला दर्ज हुआ। जांच में पता चला कि उसका पैसा कई म्यूल खातों में ट्रांसफर किया गया था, जिनमें से एक का पता गुजरात के सूरत में चला।

बांग्लादेश में 12 दिन में तीसरे हिंदू की हत्या

कपड़ा फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था,साथी स्टाफ ने गोली मारी

ढाका,30 दिसम्बर 2025। बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में एक कपड़ा फैक्ट्री के अंदर हिंदू कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीते 12 दिनों में बांग्लादेश में हिंदू की हत्या की यह तीसरी घटना है। घटना भालुका उपजिला की सुलताना स्वेटर्स लिमिटेड फैक्ट्री में हुई। मृतक की पहचान बजेंद्र बिस्वास (42) के रूप में हुई है, जो फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड था। आरोपी नोमान मिया (29) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक,दोनों फैक्ट्री में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। बातचीत के दौरान नोमान मिया ने बजेंद्र पर सरकारी शॉटगन तान दी। कुछ ही देर में बंदूक चल गई और गोली बजेंद्र की बायीं जांघ में

लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। बांग्लादेश में 2 हफ्तों में 3 हिंदू मारे गए 24 दिसंबर बुधवार रात 11:00 बजे एक हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। घटना राजबाड़ी जिले के होसेनडांगा गांव में हुई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट के तौर पर हुई। पुलिस ने बताया कि अमृत को भीड़ ने जबरन वसूली के आरोप में मार डाला।

तीन राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर कार्तिक उरांव का विश्वविद्यालय सपना पूरा करें : राष्ट्रपति मुर्मू

गुमला,30 दिसम्बर 2025। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि झारखंड, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जनजातीय समुदाय से हैं। यदि तीनों सरकारें सकारात्मक पहल करें तो महान जनजातीय नेता स्वर्गीय कार्तिक उरांव का शंख नदी तट पर विश्वस्तरीय आदिवासी शक्ति स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय का सपना साकार हो सकता है। राष्ट्रपति ने इसके लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को शंख नदी के बैरियर बगीचा में विश्वविद्यालय निर्माण समिति द्वारा आयोजित अंतरराज्यीय जन सांस्कृतिक समागम सह कार्तिक

जतरा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें झारखंड आने पर तीर्थयात्रा जैसा अनुभव होता है। कार्यक्रम में उन्होंने देश के इतिहास में अपना महान योगदान देने वाले भगवान बिरसा मुंडा, जतरा टाना भगत, परमवीर अल्बर्ट एक्का, शहीद बख्तर साय, मुंडल सिंह और कार्तिक उरांव को नमन किया।

भारतीय सेना के ध्रुव-एनजी हेलिकॉप्टर में आम नागरिक सफर करेंगे

उड्डयन मंत्री नायडू ने हरी झंडी दिखाई,मेडिकल इमरजेंसी,पर्यटन और आपदाओं में इस्तेमाल होगा

बेंगलुरु,30 दिसम्बर 2025। केंद्रीय सिविल एवएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने मंगलवार को नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलिकॉप्टर ध्रुव एनजी को हरी झंडी दिखाई। इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से उड़ान भरने से पहले, मंत्री हेलीकॉप्टर के सिस्टम और फीचर्स की जानकारी लेने के लिए पायलट के साथ कॉकपिट में भी बैठे। अधिकारियों के मुताबिक ध्रुव एनजी,एक परिष्कृत 5.5-टन, हल्का ट्विन-इंजन, मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर है जिसे भारतीय इलाके की विविध और मुश्किल जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ध्रुव हेलिकॉप्टर अब तक सिर्फ सशस्त्र बलों की जरूरतें पूरी करता रहा है। अब आम नागरिक भी इसमें सफर कर सकेंगे। इसका मकसद मेडिकल

इमरजेंसी, पर्यटन, दूरदराज के इलाकों की कनेक्टिविटी और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में हेलिकॉप्टर सेवाओं को बढ़ाना है। इससे पहले, भारतीय सेना ध्रुव हेलिकॉप्टर का पहाड़ों, रेगिस्तान और समुद्री इलाकों में अपने ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करती रही है।

सिविल और यूटिलिटी हेलिकॉप्टर बाजार पर फोकस कर रही हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड : हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजी से बढ़ रहे सिविल और यूटिलिटी हेलिकॉप्टर बाजार पर फोकस कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, एयर एम्बुलेंस, ऑफशोर ऑपरेशंस, आपदा राहत और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में मांग बढ़ रही है। इसी को देखते हुए सरकारी एयरोस्पेस कंपनी सैन्य प्लेटफॉर्म से आगे अपने दायरे का विस्तार करना चाहती है। ध्रुव-एनजी की पहली उड़ान को भारत के स्वदेशी रोटरी-विंग विमान प्रोग्राम में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। साथ ही, इसे सिविल एविएशन मार्केट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की लंबी रणनीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

बांकुड़ा रैली में ममता बनर्जी का बड़ा आरोप...एआई तकनीक का इस्तेमाल कर एसआईआर किया जा रहा

नई दिल्ली,30 दिसम्बर 2025। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में ही एसआईआर प्रक्रिया के चलते करीब 60 लोगों की मौत हुई है। बुजुर्ग लोगों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है। बांकुड़ा की जनसभा में ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले वे सोनार बांग्ला का वादा करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों को पीटा जाता है।

ममता बनर्जी बोलीं- मैं सेक्युलर हूं : इससे पहले कोलकाता में 'दुर्गा आंगन' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, 'कई लोगों ने कहा है कि मैं तुष्टीकरण कर रही हूं, लेकिन मैं सेक्युलर हूं और सभी धर्मों में विश्वास करती हूं। मुझे बंगाल से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है। हम सभी जातियों,सभी धर्मों से प्यार करते हैं। यही हमारी विचारधारा है। हर व्यक्ति को अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। धर्म व्यक्तिगत पसंद है लेकिन त्योहार सभी के लिए हैं।' ममता बनर्जी ने कहा कि 'मैं सभी धर्मों के कार्यक्रमों में जाती हूं, जब मैं गुरुद्वारे जाता हूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर मैं ईद के कार्यक्रम में जाती हूं तो कुछ लोगों को परेशानी होने लगती है।' मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर भी परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि वह लंबे समय से गंगासागर में पुल निर्माण को लेकर प्रयास कर रही थीं, लेकिन अब राज्य सरकार खुद इस परियोजना को आगे बढ़ाएगी।

एआई की मदद से किया जा रहा घोटाला

बांकुड़ा की रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, एसआईआर एक बहुत बड़ा घोटाला है और एआई तकनीक का इस्तेमाल करके एसआईआर किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि लोग, भाजपा को पश्चिम बंगाल की सत्ता में नहीं आने देंगे। टीएमसी प्रमुख ने धमकी देते हुए कहा...अगर मतदाता सूची से एक भी वैध मतदाता का नाम कटा तो उनकी पार्टी टीएमसी दिल्ली में चुनाव आयोग के ऑफिस का घेराव करेगी। जनसभा में ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा...'भाजपा कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से आते हैं। अगर ऐसा है तो क्या पहलगाम में हमला आपने कराया था? दिल्ली में जो घटना हुई, उसके पीछे कौन था? भाजपा सिर्फ एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है।'

संपादकीय

जाति निर्धारण पर नई दृष्टि

तथ्यों को नहीं किया जा सकता नजरअंदाज

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मां की जाति के आधार पर एससी प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुमति दी,भले ही पिता गैर-एससी हों। कोर्ट ने कहा कि मां की जाति पिता जितनी ही महत्वपूर्ण है। लेख में इस निर्णय पर आशंकाएं और आरक्षण व्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा की गई है। इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के पिछले फैसलों का भी जिक्र है, जो वास्तविक सामाजिक भेदभाव को महत्व देते हैं। गहन विमर्श की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

हाल में शीर्ष अदालत के एक निर्णय ने खूब सुर्खियां बटोरीं और इसे एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में उल्लेखित किया गया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने पुडुचेरी की एक नाबालिग लड़की को उसकी मां की जाति के आधार पर अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति दी, भले ही उसके पिता गैर-अनुसूचित जाति समुदाय से थे।

पीठ ने टिप्पणी दी कि मां की जाति उतनी ही महत्वपूर्ण पहचान है, जितनी पिता की। इस संदर्भ में 5 मार्च,1964 और 17 फरवरी, 2002 की राष्ट्रपति अधिसूचनाओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के साथ पढ़ने पर यह पता चलता है कि जाति प्रमाण-पत्र के लिए पात्रता मुख्य रूप से पिता की जाति और किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर व्यक्ति की आवासीय स्थिति द्वारा निर्धारित की जाती है।

उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि था कि उसका पति विवाह के बाद से ही उसके साथ उसके माता-पिता के घर रह रहा है। इस तर्क से इस तथ्य को सुस्पष्ट करना था कि उसके बच्चों ने कभी भी उच्च जाति के कथित सामाजिक लाभों का उपभोग नहीं किया।

इससे पूर्व देश की विभिन्न अदालतों ने मां की जाति के इस्तेमाल के संबंध में जब भी निर्णय दिए तो उसका मूलभूत आधार यह रहा कि क्या बच्चे उच्च जाति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक लाभों से वंचित रहे। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय पर तमाम तर्क-वितर्क के साथ अनेक आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। पहली आशंका तो यह है कि इससे आरक्षण व्यवस्था के लाभ के लिए एक नई परंपरा स्थापित हो जाएगी,जिसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। इन आशंकाओं को एक सिरे से नकारा नहीं जा सकता, परंतु जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, हम कानून के प्रश्न को खुला रख रहे हैंज। बदलते समय के साथ माता की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र क्यों जारी नहीं किया जाना चाहिए? इस प्रश्न भरे वक्तव्य के गहरे निहितार्थ हैं,परंतु त्वरित रूप से निर्णय पर पहुंचने से पूर्व इस विषय पर एक गहन विमर्श की आवश्यकता है।

यह महत्वपूर्ण है कि यह निर्णय इस बात को सामान्य सिद्धांत घोषित नहीं करता कि जाति हमेशा मां के माध्यम से ही विरासत में मिल सकती है। न ही यह निर्णय यह सिद्ध करता है कि मात्र जाति के आधार पर भविष्य में सभी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति प्रमाण-पत्र दावों को बाध्यकारी रूप से स्वीकार किया जाता रहेगा।

इस मामले को अगर समझना है तो हमें उस निर्णय का भी विश्लेषण करना होगा, जो 20 जून, 2025 को बांबे उच्च न्यायालय के 'सुजल मंगला बिरवाडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले' में न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और डा. नीला गोखले की खंडपीठ ने दिया था। चंभर (अनुसूचित जाति) श्रेणी के तहत जाति वैधता प्रमाण-पत्र की मांग करने वाली एक छात्रा की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था,'यद्यपि तलाक के बाद सुजल का पालन-पोषण उसकी माता ने किया,किंतु केवल अनुसूचित जाति के माता का होना जाति-आधारित लाभों का दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।'

कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता का पालन-पोषण विशेषाधिकार प्राप्त वातावरण में हुआ था। उसने केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और उसे सामाजिक रूप से किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था। उसकी माता की आर्थिक स्थिति और परिवार की व्यावसायिक पृष्ठभूमि ने उसके दावे को और भी कमजोर कर दिया।

गौरतलब है कि छात्रा ने अपने पिता के गैर-अनुसूचित जाति 'हिंदू कृषि' समुदाय से होने के बावजूद अपनी माता की 'चंभर' जाति के आधार पर अनुसूचित जाति का दर्जा मांगा था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जाति-आधारित आरक्षण के लिए केवल जन्म-आधारित संबंध ही नहीं, बल्कि वास्तविक भेदभाव का प्रमाण आवश्यक है। ठीक यही विचार दृष्टि फरवरी 2025 को बांबे उच्च न्यायालय के ही 'स्वानुभूति जीवराज जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य' मामले में सामने आई।

इस मामले में न्यायालय ने अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए यह कहा था कि जातिगत वैधता विवादों से संबंधित कानून को स्पष्ट करते हुए विभिन्न जातियों के माता-पिता से जन्मे बच्चे,जिनमें से माता या पिता में से कोई एक अनुसूचित जाति से संबंधित हों, बिना यह साबित किए कि उन्हें उस जाति से संबंधित वास्तविक सामाजिक भेदभाव,नुकसान या अभाव का सामना करना पड़ा है,स्वतः ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकते। रमेशभाई दभाई नाइका बनाम गुजरात राज्य (2012) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि अंतरजातीय विवाह के मामलों में जाति निर्धारण आसपास के तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वास्तव में यह एक तथ्य है कि कई बार परिवेश बहुत असर डालने वाला साबित होता है। जातिगत आरक्षण पर होने वाली बहस के बीच सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय अनेक आशंकाओं को जन्म दे रहा है।

चूंकि इस सत्य से इन्कार नहीं कि भारत के सुदूर हिस्सों में आज भी सामाजिक ढांचा जातिगत भेदभाव के बीच गुंथा हुआ है और अनेक बार जातिगत भेदभाव की अनचाही पीड़ाएं गहरे घाव कर जाती हैं,इसलिए ऐसे गंभीर मुद्दों पर गहन विमर्श के पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।

उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत का फैसला न्यायिक संवेदनशीलता पर भी प्रश्नचिह्न

सुभाष बुड़ावन वाला,
रतलाम,मध्यप्रदेश

सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाना और अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़े अपने ही आदेश को स्थगित करना केवल दो कानूनी घटनाएं नहीं हैं, बल्कि यह बदलते समय में न्यायपालिका और समाज के रिश्ते को भी रेखांकित करता है।

यह सच है कि न्यायालय स्वतंत्र होते हैं,लेकिन वे समाज से कटे हुए नहीं हो सकते। आज सोशल मीडिया के विस्तार ने आम नागरिक को आवाज दी है और यही आवाज कई बार उन फैसलों पर सवाल खड़े करती है,जो संवैधानिक मूल्यों और जनभावनाओं से टकराते प्रतीत होते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे मामले में जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म और सत्ता के दुरुपयोग का गंभीर आरोप सिद्ध हो चुका हो,वहां यह कहना कि जनप्रतिनिधि लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते,न केवल कानून की संकीर्ण व्याख्या लगती है बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति न्यायिक संवेदनशीलता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करती है।

इसी तरह अरावली पहाड़ियों को केवल सौ मीटर से ऊंचे भूभाग तक सीमित करने की परिभाषा पर्यावरण संरक्षण के दशकों पुराने प्रयासों को कमजोर कर सकती थी, क्योंकि अरावली केवल पहाड़ियों का समूह नहीं,बल्कि उत्तर भारत की पारिस्थितिकी की रीढ़ है जो भूजल संरक्षण,वायुशुद्धता और मरुस्थलीकरण रोकने में अहम भूमिका निभाती है। इन दोनों फैसलों के खिलाफ सोशल मीडिया, पर्यावरणविदों, महिला संगठनों और आम लोगों की तीखी प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि आज जनता केवल मूक दर्शक नहीं रही। यह कहना गलत नहीं होगा कि डिजिटल मंचों ने जनमत को संगठित कर न्यायिक विमर्श का हिस्सा बना दिया है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले पर पुनर्विचार करता है,तो इसे कमजोरी नहीं बल्कि न्यायिक परिपक्वता और संवैधानिक नैतिकता का उदाहरण माना जाना चाहिए। समय के साथ कानून की व्याख्या में लचीलापन और आत्म-समीक्षा की क्षमता ही किसी भी संस्था को विश्वसनीय बनाती है। हालांकि यह भी उतना ही आवश्यक है कि न्यायपालिका पर यह आरोप न लगे कि वह केवल जन दबाव में निर्णय बदलती है,इसलिए बेहतर होगा कि फैसले देते समय सामाजिक प्रभाव, संवैधानिक भावना और दीर्घकालिक परिणामों पर पहले ही गंभीरता से विचार किया जाए।

फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि आज के दौर में जनादेश केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर उस मुद्दे पर मुखर हो चुका है जो न्याय, सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़ा है। इन दोनों मामलों में जनता की चिंता को सम्मान देना सुप्रीम कोर्ट के बड़प्पन को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि लोकतंत्र में न्याय और जनभावना एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं।

शुभकामनाओं से संकल्प तक

संजीव ठाकुर,
रायपुर,छत्तीसगढ़

सशक्त बनें देश की नारी शक्ति... सशक्त भारत का नव अभियान...

नव वर्ष केवल कैलेंडर का परिवर्तन नहीं होता,यह चेतना का पुनर्जागरण होता है। नया आकाश,नई उड़ान और नई दिशा का संकेत होता है। नव वर्ष 2026 का आगमन यदि मात्र औपचारिक शुभकामनाओं, संदेशों और उत्सवों तक सीमित रह जाए,तो यह समय और अवसर दोनों के साथ अन्याय होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि यह नव वर्ष नई ऊर्जा, नई दृष्टि और ठोस कार्ययोजना का वर्ष बने–विशेषतः स्त्रियों, बच्चों और बुजुर्गों के संपूर्ण सम्मान, संरक्षण और वास्तविक अधिकारों की सुनिश्चितता के लिए। श्रेष्ठ भारत के निर्माण का मार्ग सशक्त नारी से होकर ही गुजरता है।

भारतीय संस्कृति और इतिहास में नारी को सदैव सर्वोच्च स्थान प्राप्त रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता केवल एक श्लोक नहीं, बल्कि भारतीय जीवन-दर्शन का मूल सूत्र है। जिस घर, समाज और राष्ट्र में स्त्री का सम्मान होता है, वहां समृद्धि केवल आर्थिक नहीं, बल्कि नैतिक,सांस्कृतिक और मानवीय रूप में भी पुष्पित-पल्लवित होती है। यही कारण है कि भारत को भारत माता कहा गया–यह केवल भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है।

नारी ने सदैव भारत के मान-सम्मान को वैश्विक स्तर पर ऊंचा रखा है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक असंख्य उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन पर राष्ट्र गर्व करता है। महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट का यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है–मुझे एक योग्य माता दे दो,मैं तुम्हें एक योग्य राष्ट्र दूंगा। यह कथन मातृत्व की उस शक्ति को रेखांकित करता है,जो राष्ट्र की नींव को संस्कार, अनुशासन और दायित्वबोध से सुदृढ़ करती है।

मानव कल्याण, कर्तव्य, सृजन शीलता और ममता को सर्वोपरि रखते हुए महिलाओं ने मां के रूप में राष्ट्र निर्माण की आधारशिला रखी है। महिलाएं केवल जीवन को जन्म नहीं देतीं,वे जीवन को दिशा देती हैं। बच्चों के व्यक्तित्व,चरित्र और राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में मां की भूमिका निर्णायक होती है। यही कारण है कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं का योगदान अप्रत्यक्ष होते हुए भी सबसे गहन और प्रभावशाली होता है। वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी विवेकानंद जैसी विभूतियां केवल ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं हैं,वे मातृ-संस्कारों की जीवंत प्रतिमाएं हैं। भारतीय इतिहास माताओं के त्याग, तप और दूरदृष्टि से आलोकित है। जीजाबाई ने शिवाजी जैसे राष्ट्रनायक को गढ़ा, पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ की अस्मिता बचाई,जयंताबाई जैसी माताओं ने राष्ट्रधर्म को जीवन से ऊपर रखा। माताएं ही बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं,वे बालक को केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं,बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी नागरिक बनाती हैं। इस दृष्टि से नारी राष्ट्र निर्माण की सशक्त सूत्रधार है।

नारी का स्वरूप केवल बाह्य सौंदर्य तक सीमित नहीं,वह अंतर्मन की विराटता का प्रतीक है। विविधता में एकता नारी का स्वभाव है भाषा, वेश-भूषा और संस्कृति भिन्न हो सकती है, पर स्त्री का मूल भाव करुणा,सृजन और संरक्षण में एक समान होता है। नारी प्रकृति और ईश्वर के मध्य सेतु है एक दिव्य साध्य, जिसे अनुभव करने के लिए पवित्र दृष्टि और संवेदनशील चेतना की आवश्यकता होती है। वह अमृत वरदान भी है और समाज के रोगों की दिव्य औषधि भी। सभ्यता, संस्कृति,संस्कार और परंपराओं का पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरण महिलाओं के माध्यम से ही संभव हुआ है। स्त्री ही परिवार की प्रथम शिल्पकार है और समाज की नैतिक संरक्षिका। सशक्त महिला सशक्त समाज की आधारशिला होती है–यह कथन आज के समय में केवल नारा नहीं,बल्कि विकास का व्यावहारिक सत्य है। मां शिशु की प्रथम शिक्षिका होती है,इसके बाद बहन,पत्नी और सहचरी के रूप में नारी जीवन-पथ की पथप्रदर्शक बनती है। इतिहास साक्षी है कि पत्नी चाहे तो पति को गुणवान बना सकती है और चाहे तो उसे पतन से भी बचा सकती है।

जब भी राष्ट्र पर संकट आया, पत्नियों ने अपने पतियों को तिलक लगाकर रणभूमि में भेजा और विजय का विश्वास दिया।

नए वर्ष के निर्णायक मोर्चे

अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने वाला शक्ति-केंद्र बनने की शुरुआत

वर्ष 2026 भारत की विदेश नीति के लिए निर्णायक होगा,जहाँ उसे वैश्विक सत्ता–संतुलन, आर्थिक अनिश्चितता और क्षेत्रीय अस्थिरता का सामना करना होगा। अमेरिका से व्यापारिक चुनौतियों,ब्रिक्स की अध्यक्षता,व्यापार कूटनीति, और पाकिस्तान–चीन संबंधों का प्रबंधन भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारत को संतुलन साधते हुए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने वाले शक्ति–केंद्र के रूप में उभरना है।

डॉ. मनिष दाभाडे

वर्ष 2025 को विदाई देते हुए भारत केवल एक कैलेंडर वर्ष का समापन नहीं कर रहा, बल्कि अपनी विदेश नीति के एक अत्यंत निर्णायक और चुनौतीपूर्ण चरण में कदम रख रहा है। वर्ष 2026 भारत के लिए एक सामान्य कूटनीतिक निरंतरता का वर्ष नहीं होगा, बल्कि यह वह समय होगा जब वैश्विक सत्ता-संतुलन, आर्थिक अनिश्चितता और पड़ोसी क्षेत्रों में अस्थिरता, तीनों एक साथ भारत की रणनीतिक क्षमता की परीक्षा लेंगे।

आज भारत वह देश नहीं रहा,जो वैश्विक घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता हो। वह अब एक ऐसा प्रभावशाली शक्ति-केंद्र है,जिसकी नीतियों का प्रभाव क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है। 2026 में प्रवेश करते समय भारत की विदेश नीति की सबसे तात्कालिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील चुनौती अमेरिका के साथ उसके संबंध हैं। रणनीतिक स्तर पर भारत-अमेरिका संबंध मजबूत बने हुए हैं।

चीन को लेकर साझा चिंताएं,हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग और रक्षा साझेदारी इसकी पुष्टि करते हैं,किंतु आर्थिक मोर्चे पर स्थिति कहीं अधिक जटिल है। 2025 में भारतीय निर्यात पर लगाए गए भारी अमेरिकी शुल्कों ने यह स्पष्ट कर दिया कि रणनीतिक साझेदारी अब भी आर्थिक संरक्षणवाद की गारंटी नहीं देती। यह केवल व्यापारिक नुकसान का प्रश्न नहीं है,बल्कि उस व्यापक संकेत का भी है कि अमेरिका भारत को एक रणनीतिक साझेदार के साथ-साथ एक लेन-देन आधारित आर्थिक इकाई के रूप में देख रहा है।

भारत के लिए 2026 की दहलीज पर सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह अमेरिका के साथ किसी सीमित व्यापारिक समझौते की दिशा में बढ़े, बिना यह संदेश दिए कि वह आर्थिक दबाव के आगे झुकने को तैयार है। अत्यधिक नरमी भारत की वैश्विक सौदेबाजी की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकती है, जबकि लंबे समय तक टकराव आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर ऐसे समय में जब वैश्विक मांग पहले ही मंद पड़ रही है।

बढ़ते कामकाजी जीवन के दबाव में बिखरते परिवार

ललित गर्ग
पटपड़गंज,दिल्ली

भाग-दौड़ प्रतिस्पर्धा और आकांक्षाओं से भरे आधुनिक जीवन में परिवार के लिए समय निकालना आज केवल एक भावनात्मक आवश्यकता नहीं, बल्कि सामाजिक अस्तित्व का प्रश्न बनता जा रहा है। वर्ष 2025 की विदाई और 2026 की अगवानी की इस संधि बेला में खड़े होकर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि विकास, तकनीक और कैरियर की दौड़ ने हमें सुविधा तो दी,लेकिन संबंधों की ऊष्मा धीरे-धीरे छीन ली। परिवार,जो सदियों से मनुष्य का सबसे सुरक्षित आश्रय रहा है, आज स्वयं असुरक्षा के दौर से गुजर रहा है। प्रश्न यह नहीं है कि आधुनिकता गलत है, प्रश्न यह है कि क्या आधुनिक जीवन शैली में परिवार व्यवस्था को बचाने की हमारी इच्छाशक्ति और समझ उतनी ही मजबूत है या नहीं?

व्यस्ततम,घटनाबहुल एवं कामकाजी जिंदगी जीने के साथ परिवार के लिए वक्त निकालना आज के इंसान के लिए ज्यादा जरूरी हो गया है। परिवार से यह जु ाव व्यक्ति को न केवल भावनात्मक रूप से,बल्कि शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी खुशनुमा रहने की ताकत देता है। इस सोच के बीच ताजा अध्ययन में आया यह तथ्य सचमुच चौंकाने वाला और चिंताजनक है कि काम के बोझ व परिवार को समय नहीं दे पाने से उपजी परिस्थितियों से निजात पाने के लिए साठ फीसदी से ज्यादा लोग अपनी मौजूदा नौकरी को बदलना चाहते हैं। ग्रेट प्लेस टू वर्क का यह अध्ययन भारत के कामकाजी लोगों के लिए और भी गंभीर है क्योंकि वर्क-लाइफ बैलेंस की ग्लोबल रैंकिंग में हम 42 वें स्थान पर हैं।

आज कामकाजी जीवन का दबाव इतना बढ़ चुका है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से घर में मौजूद होते हुए भी मानसिक रूप से दफ्तर में ही रहता है। डिजिटल कनेक्टि विटी ने समय और स्थान की सीमाएं मिटा दी हैं, लेकिन इसी के साथ उसने घर और कार्यस्थल के बीच की स्वाभाविक दीवार भी तोड़ दी है। मोबाइल फोन लैपटॉप और ऑनलाइन मीटिंग्स ने परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने, एक-दूसरे की बात सुनने और महसूस करने के अवसरों को सीमित कर दिया है। विडंबना यह है कि हम परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं,लेकिन उसी मेहनत की कीमत परिवार से दूरी बनाकर चुका रहे हैं।

वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को शुरू में वरदान माना गया था, लेकिन धीरे-धीरे यह भी पारिवारिक जीवन के लिए एक नई चुनौती बन गई। घर अब विश्राम और संवाद का स्थान न रहकर कार्यालय का विस्तार बन गया है। बच्चों के सामने माता-पिता लगातार स्क्रीन में उलझे रहते हैं, पति-पत्नी के बीच संवाद की जगह नोटिफिकेशन ले लेते हैं और बुजुर्गों की बातें अक्सर 'बाद में' की श्रेणी में डाल दी जाती हैं। ऐसे में परिवार एक साथ रहते हुए भी भीतर से बिखरता चला जाता है। यह बिखराव केवल भावनात्मक नहीं,बल्कि संस्कारों,परंपराओं और आपसी जिम्मेदारियों का भी है। कॉर्पोरेट कार्यशैली में बढ़ते लक्ष्य,बढ़ता प्रतिस्पर्धात्मक दबाव और बॉस संस्कृति ने व्यक्ति को लगातार यह एहसास कराया है कि यदि वह रुका तो पीछे रह जाएगा। इस डर ने जीवन की गति को इतना तेज कर दिया है कि ठहराव, आत्मचिंतन और संबंधों के लिए समय निकालना कमजोरी समझा जाने लगा है। जबकि सच यह है कि मजबूत परिवार ही व्यक्ति को मानसिक स्थिरता,आत्मविश्वास और जीवन की कठिनाइयों से जूझने की ताकत देता है। जब यह आधार कमजोर होता है,तो व्यक्ति बाहर से सफल दिखते हुए भी भीतर से टूटने लगता है।

सोशल मीडिया ने इस संकट को और गहरा किया है। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी परिवार के सदस्य अलग-अलग आभासी दुनिया में जी रहे हैं। दिखावे की खुशी,तुलना की प्रवृत्ति और निरंतर उपलब्ध रहने का दबाव रिश्तों में असंतोष और तनाव पैदा कर रहा है। हम दूसरों की जिंदगी पर नजर रखने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने घर के भीतर चल रही भावनाओं को समझने का समय ही नहीं बचा। यह स्थिति यदि यूं ही चलती रही तो परिवार केवल एक संरचना बनकर रह जाएगा, जिसमें आत्मा का अभाव होगा। ऐसे समय में आदर्श और अनुकरणीय परिवार व्यवस्था की पुनर्स्थापना कोई आसान काम नहीं है,लेकिन असंभव भी नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि करियर और परिवार एक-दूसरे के विरोधी नहीं,बल्कि पूरक हैं। यह सोच बदलनी होगी कि सफलता का पैमाना केवल पद,पैसा और प्रतिष्ठा है। यदि इन सबके बीच परिवार में संवाद, स्नेह और अपनापन नहीं है,तो ऐसी सफलता अधूरी ही नहीं, खोखली भी है। नए वर्ष में हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम अपने समय,ऊर्जा और प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करेंगे।

परिवार को बचाने के लिए किसी बड़े सिद्धांत की नहीं,बल्कि छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों की जरूरत है। घर में रहते हुए कुछ समय तकनीक से दूरी बनाना,साथ बैठकर भोजन करना,बच्चों और बुजुर्गों की बातों को ध्यान से सुनना और एक-दूसरे की भावनाओं को महत्व देना,ये सब साधारण लगने वाले कदम ही परिवार को फिर से जोड़ सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि गुणवत्ता पूर्ण समय केवल घंटों की संख्या से नहीं, बल्कि उस समय में मौजूद संवेदनशीलता और सहभागिता से तय होता है। नई परिवार व्यवस्था का अर्थ यह नहीं कि हम पुरानी परंपराओं को ज्यों का त्यों लौटा लें,बल्कि यह है कि हम आधुनिक जीवन की वास्तविकताओं के बीच संबंधों के मूल्यों को सुरक्षित रखें। जहां दोनों पति-पत्नी कामकाजी हैं, वहां जिम्मेदारियों का संतुलित बंटवारा,आपसी सहयोग और सम्मान परिवार को मजबूत बना सकता है। बच्चों को केवल प्रतिस्पर्धा की दौ के लिए तैयार करने के बजाय उन्हें भावनात्मक बुद्धिमत्ता,संवेदनशीलता और रिश्तों की अहमियत सिखाना भी उतना ही जरूरी है। बुजुर्गों को बोझ नहीं,बल्कि अनुभव और संस्कार की धरोहर मानकर सम्मान देना परिवार की आत्मा को जीवित रखता है।

कविता

नूतन वर्ष

मदन मंडावी
ढारा,डोंगरगढ़,छत्तीसगढ़

नवल,धवल,सजल,पुलकमय
सृष्टि का गोद संपन्न हरित रहे,
आशाओं को छूले जीवन तरंग
मन चंचल, सुखमय,फलित रहे,
राग,द्वेष त्याग मानव मन,तन
ना भेदभाव,ना ही निर्दिष्ट रहें,
हर्षमय का हो,जग वातावरण
भाव प्रेरित,ज्योति संचरित रहे,
निर्मल तन,नव चेतन मन वचन
निर्भय,नव सृजन,उत्कर्ष रहे,
यह नूतन वर्ष,जीवन नीति का
नव प्रसंग,उमंग सा गगन रहे ,
इस नवल वर्ष में,हे करुणानिधे
हम अपनो से ना ओझल रहें ।।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

सूरजपुर में कांग्रेस की ताकत दिखी,लेकिन गुटबाजी ने सवाल खड़े किए

भूपेश बघेल के मंच पर गरजे सवाल,संगठन में दिखी खामोशी,कार्यकर्ता सम्मेलन बना शक्ति प्रदर्शन

- भीड़ बघेल की,चुनौती कांग्रेस की...भाजपा पर हमला,कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत...
- सूरजपुर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन... भूपेश बघेल के आगमन से सियासी पारा हाई...
- कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा सरकार पर तीखा हमला,गुटबाजी भी आई सामने...

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,30 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सम्मेलन में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के शामिल होते ही सूरजपुर जिले का सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया,जिले की सीमा से लेकर सम्मेलन स्थल सेवाकुंज तक भूपेश बघेल का जोरदार और भव्य स्वागत किया गया,नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शशि सिंह के प्रथम कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इसे कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन बना दिया।

भाजपा सरकार पर तीखा हमला

सम्मेलन को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने पाँच वर्षों के कार्यकाल में 95 नई विकास योजनाओं के माध्यम से 'नवा छत्तीसगढ़' की नींव रखी, लेकिन मौजूदा सरकार उन योजनाओं को बंद करने में जुटी है, उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में अराजकता का माहौल है रोजगार और भर्तियां ठप, हर विभाग में अव्यवस्था है और अधिकारी-कर्मचारी,महिला,युवा,मजदूर व किसान आंदोलन की राह पर हैं, भूपेश बघेल ने दो टूक कहा आज लड़ाई लड़ने की जरूरत है और यह लड़ाई कांग्रेस अपने तरीके से लड़ेगी, कांग्रेस हर वर्ग–गरीब, व्यापारी,महिला,युवा,किसान और मजदूर–के साथ खड़ी है,उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने स्कूल खोले, जिन्हें अब बंद किया जा रहा है;गौठान बनाए, जिन्हें समाप्त किया जा रहा है;रोजगार के अवसर पैदा किए, जिन्हें बर्बाद किया जा रहा है,उन्होंने मनरेगा को भी 'षड्यंत्रपूर्वक बंद करने की कोशिश' बताया।

किसान और निजीकरण का मुद्दा : किसानों की स्थिति पर बोलते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि आज किसान धान बेचने के लिए मंडियों और केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं, निजीकरण के मुद्दे पर उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा किया और कांग्रेस की वैचारिक प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

संगठन को मजबूत करने का आह्वान : इस अवसर पर उन्होंने पूर्व मंत्री स्व. तुलेश्वर सिंह को याद करते हुए मंच से पूर्व विधायकों, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से अपील की कि वे जिलाध्यक्ष शशि सिंह को पूरा सहयोग दें और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करें।

जिले भर में हुआ भव्य स्वागत : सूरजपुर सीमा के संजयनगर, सिलफिली, जयनगर, बिश्रामपुर और टोल प्लाजा सहित विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक अंदाज़ में स्वागत किया, सुआ, सैला और करमा नृत्य ने कार्यक्रम को सांस्कृतिक रंग दिया, कार्यक्रम के बाद भूपेश बघेल ने विभिन्न कांग्रेस नेताओं के निवास पर पहुंचकर मुलाकात की।

आदिवासी समाज का पारंपरिक सम्मान : सम्मेलन के दौरान जिले के आदिवासी समाज ने पारंपरिक वेशभूषा में तीर-धनुष भेंट कर भूपेश बघेल का सम्मान किया, जो आयोजन का विशेष आकर्षण रहा।

सूरजपुर का संदेश : सड़क पर ताकत दिखी, संगठन में दरार क्यों?

सूरजपुर का कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं था, यह राजनीतिक मूड मीटर था,पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के आगमन ने साफ कर दिया कि आज भी कांग्रेस की सबसे बड़ी भीड़ खींचने वाली ताक़त वही हैं,सेवाकुंज में उमड़ा जनसैलाब यह बताने के लिए काफी था कि जमीन पर कांग्रेस पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसी शक्ति प्रदर्शन के बीच जो सबसे बड़ा सवाल उभरा, वह भीड़ से नहीं,खाली कुर्सियों से निकला,भूपेश बघेल ने मंच से भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला रोजगार ठप्प,योजनाएं बंद,किसान परेशान,मनरेगा खतरे में। ये आरोप नए नहीं हैं,लेकिन भीड़ की तालियों ने बताया कि जनता इन बातों से खुद को जोड़ रही है। कर्मचारी,किसान युवा और मजदूर–हर वर्ग में असंतोष है और कांग्रेस इसे अपना राजनीतिक ईंधन बनाना चाहती है।

क्या कांग्रेस खुद अपने घर में एकजुट है?

सम्मेलन में पैलेस खेमा की गैरहाजिरी केवल संयोग नहीं,बल्कि संगठनात्मक बीमारी का लक्षण है,तीनों विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े कई बड़े चेहरे नदारद रहे,यह चुप्पी उतनी ही शोर करती है जितनी मंच से की गई भाषणबाजी,कांग्रेस अगर 2028 की तैयारी कर रही है, तो उसे यह समझना होगा कि भीड़ चुनाव नहीं जिताती, संगठन की एकजुटता जिताती है, भूपेश बघेल का संदेश साफ था लड़ाई लड़नी होगी,लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है क्या यह लड़ाई भाजपा से होगी या कांग्रेस के भीतर ही? अगर शक्ति प्रदर्शन के साथ शक्ति-संतुलन नहीं साधा गया,तो सूरजपुर जैसा आयोजन इतिहास में एक 'भव्य कार्यक्रम' बनकर रह जाएगा,राजनीतिक टर्निंग पॉइंट नहीं।

सूरजपुर में बनेगा राजीव भवन

जिलाध्यक्ष शशि सिंह के आग्रह पर भूपेश बघेल ने घोषणा की कि सूरजपुर जिले में राजीव भवन का निर्माण जल्द होगा। भवन की लागत का आधा हिस्सा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और आधा स्थानीय सहयोग से जुटाया जाएगा। इस अवसर पर भूपेश बघेल ने स्वयं एक लाख रुपये का सहयोग राशि प्रदान की।

पैलेस खेमा नदारत,गुटबाजी फिर चर्चा में...

सम्मेलन में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी भी खुलकर सामने आई,भूपेश बघेल के प्रवास के दौरान पैलेस समर्थक खेमा बड़ी संख्या में नदारत रहा, प्रेमनगर,प्रतापपुर और भटगांव विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े कई प्रमुख चेहरे—पूर्व मंत्री,पूर्व सांसद,पूर्व विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और एनएसयूआई पदाधिकारी—कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जिलाध्यक्ष परिवर्तन के बाद से लगातार सामने आ रही यह स्थिति संगठनात्मक एकजुटता के लिए चुनौती मानी जा रही है।

ई-रिक्शा चोरी..आरोपी को पकड़ा,पुलिस कर रही है जांच

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास एक ई-रिक्शा चोरी हो गया,जिसे कुछ ही समय में मालिक ने खोज निकाला और आरोपी को पकड़ लिया। यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 12.30 बजे हुई, जब ठाकुरपुर निवासी वीरेन्द्र सिंह ने अपनी पत्नी के नाम पर पंजीकृत ई-रिक्शा को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर खड़ा किया और चाबी लगाकर पास में ही कुछ काम से चले गए। इसी दौरान,पलभर में उनका ई-रिक्शा गायब हो गया। ई-रिक्शा चोरी की जानकारी मिलने के बाद वीरेन्द्र सिंह ने अस्पताल के पुलिस सहायता केन्द्र और अपने परिवार के सदस्यों को सूचित किया। इसके बाद,वह दूसरे ऑटो वाहन में सवार होकर ई-रिक्शा की खोजबीन करने निकले। उन्होंने मणिपुर स्कूल के पास एक व्यक्ति को ई-रिक्शा लेकर जाते देखा,और फिर संगम चैक के पास उसे पकड़ लिया। ई-रिक्शा के स्वामी ने पुलिस को सूचना दी,और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

बाइक की ठोकर से घायल युवक की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

बाइक की ठोकर से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गढ़वा जिले के रमना थाना अंतर्गत ग्राम सिलीदाग निवासी शिवम कुमार देव पिता संजय कुमार सिंह 20 वर्ष,अपने ठेकेदार जीजा प्रेमजीत सिंह के साथ लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सलका, पलका में चल रहे पाइप लाइन विस्तार के काम को देखने के लिए गया था। यहां सडक़ के किनारे 4-5 लोग खड़े थे,इसी दौरान उदयपुर की ओर से आ रहा बाइक क्रमांक सीजी 15 डीएम 4115 में सवार एक व्यक्ति पीछे से शिवम को ठोकर मार दिया,जिसमें उसे गंभीर चोटें आई थी। घायल अवस्था में उसे उदयपुर स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया, यहां से प्राथमिक चिकित्सा के बाद रेफर करने पर स्वजन मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे,यहां इलाज के दौरान 29 दिसम्बर की रात 8.50 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

3 वर्षीय मासूम ने चूहा मार दवा को चॉकलेट समझकर खाया,मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

घर में खेल रहा तीन वर्षीय मासूम चूहा मार दवा को चाकलेट समझकर चबाने लगा। परिजन की नजर पड़ी और उसे अस्पताल लेकर पहुंचे,इलाज के दौरान वह दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम घूचापुर निवासी अजय सिंह का 3 वर्षीय पुत्र गितांशु सिंह 24 दिसम्बर की शाम को घर में खेल रहा था,इस दौरान चूहा मारने के लिए रखे दवा को चाकलेट समझकर मुंह में डाल लिया। बच्चे को कुछ खाते देखकर स्वजर पहुंचे और मुंह से चूहा मार दवा को निकाले।

भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ को उजाडने की रच रही साजिश : भूपेश बघेल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान सरगुजा में कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। उनके आगमन पर कांग्रेस पार्टी के भीतर एक गुटबाजी भी देखने को मिली, जिससे राजनीतिक माहौल गरम हो गया। जहां एक गुट ने उनका स्वागत किया, वहीं जिला कांग्रेस कमेटी इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रही। इस मुद्दे पर भूपेश बघेल ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि वे यहां किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं, बल्कि एक पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं। भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ को 'उजाडने' की साजिश रच रही है। उनका कहना था कि सरगुजा में एसईसीएल परियोजना के प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिया गया और इसके बावजूद जमीन की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया, जिसके चलते स्थानीय लोग आक्रोशित हुए और लाठीचार्ज जैसी घटनाएं हुईं। रायगढ़ जिले के तमनार इलाके में भी उन्होंने भाजपा सरकार पर कटाक्ष किया, जहां 14 दिन से हड़ताल कर रहे लोगों की आवाज नहीं सुनी गई और इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। भूपेश बघेल ने इस घटनाक्रम को प्रदेश सरकार की असंवेदनशीलता का प्रमाण बताया और आरोप लगाया कि यह स्थिति हर जगह बन रही है, जिससे लोगों में आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ शांतिपूर्ण प्रदेश रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार के राज में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस दौरान उन्होंने रामगढ़ पहाड़ का उल्लेख भी किया, जहां उन्होंने इसे 5000 साल पुराना ऐतिहासिक धरोहर बताया और कहा कि इसे राम वनगमन पर्यटन परिपथ में शामिल कर सौंदर्यीकरण किया गया था। लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा इस तरह के ऐतिहासिक धरोहरों को नष्ट करने का आरोप उन्होंने लगाया। एक और विवादास्पद बयान देते हुए भूपेश बघेल ने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबा शास्त्री लोगों से चंदा लेने की गतिविधि बंद करें। उनका आरोप था कि ये लोग अंधविश्वास फैलाते हैं और धन की उगाही करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आकर केवल धार्मिक ज्ञान की बातें करें, न कि अंधविश्वास का प्रचार करें। भूपेश बघेल ने यहां तक कहा कि अगर पर्ची पर विश्वास होता, तो बाबा शास्त्री खुद अस्पताल में बैठकर इलाज करते और प्रदूषण भी खत्म कर देते। इसके बाद, भूपेश बघेल ने सूरजपुर के लिए अपनी यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे वहां शशि सिंह से मिलने जा रहे हैं,जो अब सूरजपुर की कांग्रेस अध्यक्ष बनी हैं। बघेल ने यह भी बताया कि वे पेंड्रा-मरवाही जाएंगे। भूपेश बघेल ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके सरगुजा दौरे का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था,बल्कि यह एक पारिवारिक कार्यक्रम था। कार्यक्रम में सरगुजा जिले के कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के अनुपस्थित रहने पर उन्होंने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और कहा कि यह किसी राजनीतिक कार्यक्रम से जुड़ा नहीं था। इस तरह से भूपेश बघेल का यह दौरा कई मुद्दों पर चर्चा का केंद्र बन गया,जिसमें प्रदेश की राजनीति, भाजपा सरकार की नीतियां और धार्मिक संस्थाओं के कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणियां शामिल थीं।

अंबिकापुर के ग्राम सरगवां में बकरों की बलि और रेबीज का खतरा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

अंबिकापुर के पास स्थित ग्राम सरगवां में एक अजीबो-गरीब घटना सामने आई,जिससे गांव में हडक़ंप मच गया। यहां परंपरागत पूजा के दौरान बकरों की बलि दी गई और उनका मांस गांववासियों को प्रसाद के रूप में खिलाया गया। लेकिन बाद में यह खुलासा हुआ कि जिन बकरों की बलि दी गई थी,उनमें से एक बकरा एक रेबीज संक्रमित कुत्ते द्वारा काटा गया था। यह खबर फैलते ही गांव में डर का माहौल बन गया, क्योंकि 400 से ज्यादा ग्रामीणों ने वह मांस खाया था। ग्राम सरगवां में 28 दिसंबर को परंपरागत पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें गांव के देवी-देवताओं की पूजा की जाती है और बकरों की बलि दी जाती है। इस पूजा में करीब 12 से 15 बकरों की बलि दी गई थी और इन बकरों का मांस प्रसाद के रूप में लगभग 400 ग्रामीणों को बांटा गया था। कुछ समय बाद यह जानकारी सामने आई कि इनमें से एक बकरा रेबीज संक्रमित कुत्ते द्वारा काटा गया था, जिससे गांव में चिंताएं बढ़ गईं। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच नारायण प्रसाद और उपसरपंच कृष्णा सिंह ने बकरों की खरीदारी गांव के ही नान्हू राजवाड़े से की थी। नान्हू को यह जानकारी थी कि एक बकरा रेबीज संक्रमित कुत्ते से प्रभावित हुआ था,लेकिन उसने इस बात को जनप्रतिनिधियों से छुपाया। अब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं वे और उनके परिवार के लोग रेबीज की चपेट में न आ जाएं। इस भय के चलते गांव के लोग एंटी-रेबीज वैक्सीन लेने की तैयारी में हैं। इस डर के मद्देनजर, मंगलवार को गांव के लोग सीएमएचओ से मिले और स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की मांग की। प्रशासन ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 31 दिसंबर को एक स्वास्थ्य शिविर लगाने का निर्णय लिया, जिसमें ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी।

ग्राम सरगवां में यह पूजा हर तीसरे साल आयोजित की जाती है। यह एक धार्मिक परंपरा है, जिसमें बकरों की बलि दी जाती है और उनका मांस प्रसाद के रूप में गांव के पुरुषों को वितरित किया जाता है। हालांकि, इस बार यह परंपरा एक गंभीर समस्या का कारण बन गई,क्योंकि इस पूजा के दौरान मांस खाने से स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकता था। पशु चिकित्सक डॉ. चंदू मिश्रा ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर बकरा रेबीज संक्रमित था, तो भी अगर उसका मांस अच्छी तरह से पकाया गया हो,तो उसमें रेबीज के वायरस के प्रभाव से बचाव होता है। उचित तापमान पर मांस पकाने से रेबीज के वायरस मर जाते हैं। हालांकि,एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य जांच जरूरी है ताकि कोई भी संभावित खतरा टाला जा सके। इस घटना ने न केवल सरगवां गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी एक चेतावनी का संकेत दिया है कि धार्मिक परंपराओं के साथ-साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इस घटना के बाद से गांववाले अब इस बात को लेकर जागरूक हो गए हैं कि भविष्य में ऐसे किसी भी आयोजन में स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।

कड़ाके की ठंड,शीतलहर का अलर्ट अंबिकापुर का तापमान 3.5 डिग्री

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

इस समय सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड का असर काफी गहरा है, और अंबिकापुर शहर में तो तापमान ने इस सीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोमवार की रात अंबिकापुर में तापमान 3.5 डिग्री तक गिर गया, जो इस सीजन की सबसे सर्द रात साबित हुई। वहीं, आसपास के पाट इलाकों में तापमान डेढ़ डिग्री के आसपास बना हुआ है। ठंड की इस तीव्रता के कारण पत्तों, फूलों, घास और पुआल पर ओंस की बूंदें जम रही हैं। दिन में भी लोग गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलने को मजबूर हो रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल के मुताबिक, उत्तर दिशा से आने वाली शुष्क हवाओं के कारण यह सर्दी पड़ रही है। इन हवाओं का सिलसिला लगातार जारी रहने से, और तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। इसके अलावा, 31 दिसंबर तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि ठंड से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। यह मौसम बच्चों और बुजुर्गों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।

इस सर्दी से निपटने के लिए अंबिकापुर नगर निगम ने शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है। यह अलाव ठंड से राहत पाने का एकमात्र उपाय बन गए हैं। लोग शाम और रात के अलावा, दिन में भी इन अलावों के पास बैठकर गर्मी महसूस करते दिख रहे हैं। इसके अलावा,लोग अपने घरों में भी अलाव और रूम हीटर का सहारा ले रहे हैं।

CMYK

झोला छाप और अवैध क्लिनिकों पर करें सख्त कार्यवाही : कलेक्टर

-संवाददाता-
बलरामपुर,30 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा की उपस्थिति में संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति (एनसीओआरडी) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर प्रभावी रोक लगाने तथा संबंधित विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री वैभव बैंकर, वनमण्डलाधिकारी श्री आलोक वाजपेयी सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाना प्रशासन की प्राथमिकता है।

उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ निरंतर कार्यवाही करने निर्देश दिए। कलेक्टर ने कोटपा एक्ट के प्रभावी प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सघन निरीक्षण कर वहां संचालित दुकानों की नियमित जांच करने को कहा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों में भी कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को प्रतिबंधित दवाओं, एक्सपायर दवाओं और संचालित क्लीनिकों के लाइसेंस की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध या अनुचित दवा का बिक्री न हो और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने अवैध क्लिनिक पर सख्त कार्यवाही करने के साथ ही झोला छाप डॉक्टरों एवं झाड़ फूक करने वाले पर भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक श्री वैभव बैंकर ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बैठक में आमजनों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर जागरूक करने की बात कही। साथ ही जिला मुख्यालय में स्थित नशा मुक्ति केंद्र को और अधिक प्रभावी बनाने आवश्यक निर्देश भी दिये।

अनुशासनहीनता एवं आचरण नियम के उल्लंघन पर संविदा शिक्षक की सेवा समाप्त

-संवाददाता-
बलरामपुर,30 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

विभिन्न माध्यमों के अनुसार स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मिडियम स्कूल में रघुनाथनगर में पदस्थ शिक्षक पीयूष वर्मा(संविदा) के द्वारा स्कूल में अध्ययनरत छात्र की पिटाई करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर द्वारा प्रस्तुत जांच में शिक्षक पीयूष वर्मा के द्वारा छात्र की पिटाई करना प्रमाणित हुई। साथ ही संस्था के प्राचार्य के द्वारा भी शिक्षक पीयुष वर्मा द्वारा सूचित किए बिना अवकाश में रहने, सिलेबस अनुसार कोर्स व शिक्षक दैनन्दनी पंजी पूर्ण न करने सहित अभद्र व्यवहार करने अन्य तथ्यों के लिए नोटिस जारी किया गया था। साथ ही स्कूल में अन्य सह कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने की भी शिकायत की गई थी। जांचकर्ता अधिकारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत प्रमाणित पाया जाना एवं प्राचार्य सेजेस इंग्लिस मिडियम रघुनाथनगर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार श्री पीयूष कुमार वर्मा, शिक्षक के विरूद्ध उपरोक्त साक्ष्य प्रमाणित होने के कारण श्री वर्मा उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 01, 02 एवं 03 के उल्लंघन में दोषी है।

प्राचार्य, स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट विद्यालय रघुनाथनगर द्वारा प्रस्तुत सहपत्रों अनुसार प्रेषित प्रस्तावों एवं श्री पीयूष कुमार वर्मा, शिक्षक के विरूद्ध जांचकर्ता अधिकारी एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर के अनुसार उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 की दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा श्री पीयूष कुमार वर्मा, शिक्षक-संविदा (अंग्रेजी माध्यम) विषय कला, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रघुनाथनगर को संविदा सेवा से पदच्युत किया गया है।

छ.ग. राज्य युवा उत्सव-2025 में सरगुजा का दबदबा

सरगुजा के रॉक बैंड टीम इकतारा द फ्यूजन बैंड प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

छ.ग. राज्य द्वारा आयोजित 'युवा उत्सव-2025 के इस वर्ष राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र, बहतराई, बिलासपुर में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के सभी जिलों से अलग-अलग विधाओं में अपनी अपनी प्रस्तुती दी । सरगुजा से भी Rock Band Team 'इकतारा द फ्यूज़न बैंड ने - बलरामपुर ज़िले का नेतृत्व कर राज्य में लगातार दूसरी बार अपना नाम द्वितीय स्थान पर संरक्षित कर शहर एवं जिले को गौरवानवित किया है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रॉक बैंड विधा में लगभग 33 टीम ने अपनी प्रस्तुति दी। जिसमें रॉक बैंड टीम इकतारा फ्यूजन बैंड के टिम ने

बलरामपुर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए बिलासपुर में हुए प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया उक्त टीम का नेतृत्व दीपक कुमार वसूले ने किया तथा टीम के सदस्य राहुल विश्वकर्मा, दिव्यम दास,राहुल मंडल,शौर्य सर्राफ, राहुल गुप्ता,अंकुश दास ने भाग लेकर उक्त स्थान प्राप्त किया तथा सभी ने अपने इस सफलता का श्रेय जिला प्रशासन एवं खेल व युवा कल्याण विभाग को देते हुवे समस्थ टीम ने सहर्ष धन्यवाद प्रेषित किया है ।

आपका पूंजी आपका अधिकारी अभियान के तहत DEAF दावा शिविर संपन्न

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा 'आपका पूंजी आपका अधिकारी' योजनान्तर्गत हितग्राहियों के एवं शासकीय विभागों के 10 वर्ष से अधिक लेन-देन नहीं हुये छ्श्ख्र खातों की जमा राशि को खातों को आपरेटिव कराने के उपरांत हितग्राहियों को राशि सौंपने तथा शासकीय विभागों की राशि को शासन के खाते में जमा करने एवं नॉन आपरेटिव खातों को आपरेटिव करा कर यदि योजना संचालित हो तो उपयोग किये जाने एवं योजना बंद होने की स्थिति में शासन के खातें मे राशि जमा किया जाना है। इस संबंध में 29 दिसम्बर को जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित कैम्प में जिले के सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित हुये। कैम्प अन्तर्गत 04

हितग्राहियों श्री अजीत मंडल, श्रीमती अमरावती, मोहम्मद मिर्जा अहमद एवं श्रीमती गीता के प्रकरणों का निराकरण कर राशि रूपये 915133.00 का सर्टिफिकेट किया गया। इसी कड़ी में शासकीय विभागों के 11 खातों का निराकरण कर रूपये 20766133.00 शासकीय खाते में जमा किया गया। कैम्प कलेक्टर श्री अजीत वसंत के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ जिसमें महाप्रबंधक आरबीआई रायपुर, वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख तथा सभी बैंकों के प्रतिनिधि व सहायक कोषालय अधिकारी उपस्थित रहे।

फसल गिरदावरी में लापरवाही पटवारी को पड़ी भारी,कलेक्टर ने किया निलंबित

-संवाददाता-
बलरामपुर,30 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के बलरापुर जिले में पटवारी को फसल गिरदावरी कार्य में लापरवाही भारी पड़ गई। रामचंद्रपुर तहसील में पदस्थ पटवारी विवेक शुभम वैभव के खिलाफ निंलबन का एक्शन लिया गया है. इस संबंध में कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने आदेश जारी किया है। दरअसल, रामचंद्रपुर तहसील में फसल गिरदावरी में लापरवाही की शिकायत सामने आने पर जांच कराई गई। जांच में पटवारी विवेक

शुभम वैभव की लापरवाही और उदासीनता पाई गई। जिसे छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (1) (2) (3) के विपरित माना गया. पटवारी को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला बलरामपुर-रामानुजगंज भेज दिया गया है।

अवैध धान पर की गई कार्यवाही... 134 बोरी अवैध धान किया गया जब्त

-संवाददाता-
बलरामपुर,30 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी श्री देवेन्द्र प्रधान के नेतृत्व में विकासखण्ड राजपुर अंतर्गत 24 बोरी अवैध धान जब्त किया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम कोदौरा में अवैध धान परिवहन की सूचना मिलने पर मौके में पहुंच कर 24 बोरी अवैध धान सहित 1 ट्रैक्टर जप्त कर मण्डी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए जब्त धान को चौकी डौरा को सुपुर्द किय गया। इसी प्रकार ग्राम कोटीडीह में कृषक प्रदीप गुप्ता के घर में 110 बोरी अवैध धान भण्डारित करके रखा गया था जिसे जब्त किया गया। इस दौरान तहसीलदार नरेन्द्र कुमार कवर, श्रीमती कावेरी मुखर्जी सहित संयुक्त टीम मौजूद रही। गौरतलब है कि जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने तथा अवैध धान परिवहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।

शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु 12 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

खाद्य अधिकारी ने बताया कि नगर पालिक निगम अम्बिकापुर के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु पात्र संस्था/एजेन्सी को आबंटित किया जाना है। जिसमें शासकीय उचित मूल्य दुकान नमनाकला वार्ड क्र. 14 आई.डी. 391001048, मंगल पाण्डेय वार्ड क्र. 13 आई.डी. 391001005, डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड क्र. 45 आई.डी. 391001072, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड क्र. 04, आई.डी. 391001004, स्वामी विवेकानंद वार्ड क्र. 35, आई.डी. 391001010, शीतला वार्ड क्र. 32 आई.डी. 391001030, पटपरिया वार्ड क्र. 11 आई.डी. 391001037, एवं लरंग साय वार्ड क्र. 24 आई.डी. 391001071 संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

इन शासकीय उचित मूल्य दुकानों के नवीन आबंटन के संचालन हेतु इच्छुक पात्र एजेन्सी अपना आवेदन पत्र विहित प्रारूप में सम्पूर्ण विवरण एवं दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति के साथ 12 जनवरी 2026 तक कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा में जमा कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

व्यापार समाचार

दिन भर उतार-चढ़ाव के बाद गिरकर बंद हुआ घरेलू शेयर बाजार,निवेशकों को 22 हजार करोड़ की लगी चपत

नई दिल्ली,30 दिसम्बर 2025। दिन भर उतार-चढ़ाव का सामना करने के बाद घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को सांकेतिक कमजोरी के साथ बंद हुआ। मंगलवार को कारोबार की शुरुआत भी मामूली गिरावट के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद दिन भर तेजड़ियों और मंदड़ियों के बीच एक दूसरे पर हावी होने के लिए खींचतान होती रही, जिसके कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल भी लगातार ऊपर नीचे होती रही। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.02 प्रतिशत और निफ्टी 0.01 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुए।

मंगलवार को दिन भर के कारोबार के दौरान रियल्टी, डिफेंस और आईटी सेक्टर के शेयरों में लगातार बिकवाली होती रही। इसी तरह कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, हेल्थकेयर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ऑयल एंड गैस तथा टेक इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए। दूसरी ओर बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और मेटल सेक्टर के शेयरों में लगातार लिवाली होती रही। ब्रॉडर मार्केट में भी मंगलवार को ज्यादातर समय बिकवाली का दबाव बना रहा, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.05 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ मंगलवार को कारोबार का अंत किया। मंगलवार को शेयर बाजार में आई कमजोरी के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में 20 हजार करोड़ रुपये

से भी अधिक की कमी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन मंगलवार को कारोबार के बाद घट कर 471.93 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया। जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 472.15 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को मंगलवार को कारोबार से करीब 22 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। मंगलवार को दिन भर के कारोबार में बीएसई में 4,347 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 1,921 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2,258 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 168 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में मंगलवार को 2,845 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1,233 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में और 1,612 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 12 शेयर बढ़त के साथ और 18 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 17 शेयर हरे निशान में और 33 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स मंगलवार को 94.55 अंक की कमजोरी के साथ 84,600.99 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होते ही लिवालों और बिकवालों के बीच एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस सूचकांक की चाल में उतार चढ़ाव होने लगा। खरीदारी के सपोर्ट से सेंसेक्स 111.45 अंक की मजबूती के साथ 84,806.99 अंक तक पहुंचा। बिकवाली का दबाव बनने पर सेंसेक्स 224.60 अंक की कमजोरी के साथ 84,470.94 अंक तक गिर भी गया। दिन भर हुई खरीद बिक्री के बाद सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 200 अंक से अधिक की रिकवरी करके 20.46 अंक की मामूली गिरावट के साथ 84,675.08 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह ही एनएसई के निफ्टी ने मंगलवार को 1.20 अंक की सांकेतिक गिरावट के साथ 25,940.90 अंक के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलते ही तेजड़ियों और मंदड़ियों के बीच खींचतान शुरू हो गई, जिससे इस सूचकांक की चाल भी ऊपर नीचे होने लगी। खरीदारी के सपोर्ट से निफ्टी 34.65 अंक उछल कर 25,976.75 अंक तक पहुंचा। वहीं बिकवाली का दबाव बनने पर ये सूचकांक ऊपरी स्तर से करीब 100 अंक टूट कर 64.10 अंक की गिरावट के साथ 25,878 अंक तक आ गया। दिन भर हुई खरीद बिक्री के बाद निफ्टी दिन के निचले स्तर से 60 अंक से अधिक सुधर कर 3.25 अंक की मामूली कमजोरी के साथ 25,938.85 अंक के स्तर पर बंद हुआ। पूरे दिन के कारोबार के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से श्रीराम फाइनेंस 2.50 प्रतिशत, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 2.21 प्रतिशत, बजाज ऑटो 2.15 प्रतिशत, टाटा स्टील 2.03 प्रतिशत और महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.90 प्रतिशत की मजबूती के साथ मंगलवार को टॉप 5 गेनर्स की सूची में शामिल हुए। दूसरी ओर, मैक्स हेल्थकेयर 2.19 प्रतिशत, एटरनल 2.03 प्रतिशत, इंफोसिस 1.40 प्रतिशत, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 1.36 प्रतिशत और अपोलो हॉस्पिटल 1.33 प्रतिशत की कमजोरी के साथ आज के टॉप 5 लूजर्स की सूची में शामिल हुए।

डीएफएस सचिव ने अधिकरणों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला

नई दिल्ली,30 दिसम्बर 2025। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों (डीआरएटी) के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया। डीएफएस सचिव एम. नागराजू की अध्यक्षता में अयोजित इस बैठक में अधिकरणों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला गया। वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि डीएफएस के सचिव एम. नागराजू ने इस बैठक में उपस्थित डीएफएस के वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों और भारतीय बैंक संघ के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। डीएफएस सचिव ने अधिकरणों की प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए विभाग द्वारा डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए प्रमुख कदमों पर प्रकाश डाला,जिसमें अनिवार्य ई-फाइलिंग को अपनाना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग, हाइब्रिड सुनवाई आदि शामिल हैं।

बैठक में अपीलीय अधिकरणों में वसूली प्रक्रिया की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए व्यापक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस चर्चा में शामिल थेः- डीआरटी के माध्यम से वसूली बढ़ाने के लिए बैंकों के सुदृढ़ीकरण, निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र को और मजबूत करने हेतु उपाय,वसूली को अनुकूलित करने के लिए डीआरटी में उच्च मूल्य वाले मामलों पर विशेष ध्यान देना, विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए वैकल्पिक समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालतों का अधिकतम उपयोग, डीआरटी में निपटान में सुधार के लिए आगे की प्रक्रिया में सुधार और विभाग और बैंकों द्वारा क्षमता निर्माण के लिए उपायों में पीठासीन अधिकारियों, वसूली अधिकारियों, रजिस्ट्रारों और बैंकों के अधिकृत अधिकारियों के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। मंत्रालय के मुताबिक बैठक में ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम,1993 और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में संशोधन संबंधी सुझावों पर चर्चा की गई, ताकि इन कानूनों की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सके। धिकरणों से अन्य डीआरटी में अपनाई जाने वाली ऋण वसूली के मामलों के प्रभावशाली निपटान की सर्वोत्तम विधियों को सीखने का आग्रह किया है।

छत्तीसगढ़ बना आंदोलनगढ़

सड़कों पर कर्मचारी, फाइलों में सरकार

-राजन पाण्डेय-

कोरिया/एमसीबी,30 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर चल रही प्रदेशव्यापी तीन दिवसीय हड़ताल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है, एक ओर कोरिया जिले में मशाल रैली और जनसैलाब ने आंदोलन को धार दी, वहीं दूसरी ओर मनेंद्रगढ़ (एमसीबी) में हड़ताल के समर्थन पर तीन कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम किया है, फेडरेशन ने साफ कर दिया है कि 'कलम बंद, काम बंद' आंदोलन किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा।

मशाल रैली से पुलिस कार्रवाई तकः कर्मचारी आंदोलन बनाम प्रशासन

हड़ताल का समर्थन पड़ा महंगा,मनेंद्रगढ़ में तीन कर्मचारियों पर एक्शन

कलम बंद-काम बंद-चेतावनी नहीं,हकीकत है...वादों की गारंटी फेल, आंदोलन की गारंटी चालू

800 दिन बाद भी अधूरे वादे,सरकार कटघरे में...संवाद की जगह दमन? कार्रवाई से भड़का कर्मचारी गुस्सा

छत्तीसगढ़ बना आंदोलनगढ़ : कर्मचारी फेडरेशन की हड़ताल उग्र,मशाल रैली से सड़कों पर जनसैलाब

मनेंद्रगढ़ में कार्रवाई से भड़का आक्रोश, 'कलम बंद-काम बंद' जारी...

किन कर्मचारियों पर गिरी गाज

गोपाल सिंह, व्यायाम शिक्षक
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
बेलबहरा,विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़

- आरोप-कलेक्ट्रेट में लिपिकों को शासकीय कार्य से रोकना
- कार्रवाई- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 के उल्लंघन पर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-09 के तहत निलंबन
- निलंबन मुख्यालय- जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

सुरेन्द्र प्रसाद, सफाई कर्मचारी
(नगर पंचायत झगराखाण्ड)
आरोप-कलेक्ट्रेट कार्यालय में शासकीय कार्य में बाधा
निलंबन मुख्यालय-नगर पालिका परिषद, मनेन्द्रगढ़

संजय पाण्डेय
सहायक राजस्व निरीक्षक (नगर पंचायत झगराखाण्ड)
आरोप- कलेक्ट्रेट में शासकीय कार्यों में व्यवधान
निलंबन मुख्यालय- नगर पालिका परिषद, मनेन्द्रगढ़
तीनों निलंबित कर्मचारियों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

एमसीबी में सख्ती से गरमाया आंदोलन, फेडरेशन ने बताया दमनात्मक कदम

छत्तीसगढ़ में अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की तीन दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल के बीच एमसीबी जिले में जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में तीन शासकीय कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया, जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है, जिला प्रशासन के अनुसार, 30 दिसंबर 2025 को कलेक्ट्रेट कार्यालय मनेन्द्रगढ़ चिरमिरीभरतपुर में कार्यरत लिपिकों को शासकीय कार्य करने से रोके जाने और कार्यालयीन कामकाज में व्यवधान की शिकायत सामने आई, इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए एक के बाद एक कार्रवाई की गई।

गुलाब कमरो की तीखी प्रतिक्रिया

पूर्व विधायक एवं ट्रेड यूनियन काउंसिल छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष गुलाब कमरो ने कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा यह लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है, ऐसी कार्रवाइयों से कर्मचारियों की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। हम पूरी मजबूती से कर्मचारियों के साथ खड़े हैं।

कोरिया में उग्र प्रदर्शन,मशाल रैली से सरकार को चेतावनी

कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित प्रेमाबाग धरनास्थल से कुमार चौक तक निकाली गई मशाल रैली में हजारों अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए, रैली के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई,भीड़ के कारण कुमार चौक पर यातायात बाधित रहा और राजीव भवन-रेस्ट हाउस मार्ग अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो गया,हड़ताल को कांग्रेस का खुला समर्थन मिला। जिला कांग्रेस कमेटी कोरिया के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता और कांग्रेस नेता आशीष डबरे धरनास्थल पहुंचे, प्रदीप गुप्ता ने कहा कि चुनाव के दौरान कर्मचारियों से किए गए 11 सूत्रीय वादे–अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, केंद्र के समान डीए, समयमान वेतनमान,वेतन विसंगति का निराकरण–800 दिन बाद भी अधूरे हैं। उन्होंने इसे मोदी की गारंटी का फेल होना बताया,आशीष डबरे ने आरोप लगाया कि प्रदेश में रोजगार सहायक,पटवारी, पंचायत सचिव,आंगनबाड़ी,मितानिन, एनएचएम कर्मी,शिक्षक,सफाईकर्मी सहित लगभग साढ़े चार लाख कर्मचारी आंदोलनरत हैं,जो सरकार के दावों की सच्चाई उजागर करता है।

छत्तीसगढ़ : वादों की सरकार या आंदोलन की प्रयोगशाला?

छत्तीसगढ़ आज एक असहज सच्चाई के सामने खड़ा है, जिस प्रदेश में सरकार ने गारंटी के नाम पर भरोसा मांगा था,उसी प्रदेश की सड़कों पर आज मशालें जल रही हैं, फाइलें बंद हैं और कर्मचारी खुली चेतावनी दे रहे हैं,अब और नहीं,अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की तीन दिवसीय हड़ताल केवल वेतन या भत्तों की मांग नहीं है,यह उस टूटे भरोसे का प्रतीक है जो सत्ता और कर्मचारियों के बीच बनना चाहिए था,11 सूत्रीय मांगें नई नहीं हैं,ये वर्षों से लंबित हैं। चुनाव बीत गए,सरकार बन गई, लेकिन समाधान फाइलों में कैद रह गए,कोरिया में मशाल रैली और मनेंद्रगढ़ में हड़ताल समर्थकों पर कार्रवाई,ये दो घटनाएं मिलकर एक सवाल खड़ा करती हैं।

क्या असहमति अब 'शांति भंग' मानी जाएगी?

लोकतंत्र में विरोध अपराध नहीं होता। हड़ताल का समर्थन करना,संवाद की अपील करना,आवाज़ उठाना,ये संविधान प्रदत्त अधिकार हैं। लेकिन जब कलेक्टर कार्यालय में समर्थन मांगने पर पुलिस बुला ली जाती है, तो संदेश साफ जाता है,संवाद नहीं,दमन, सबसे चिंताजनक यह है कि सरकार अभी भी हालात को कंट्रोल में बताने की कोशिश कर रही है, जबकि ज़मीनी हकीकत इसके उलट है। रोजगार सहायक से लेकर शिक्षक,आंगनबाड़ी से लेकर सफाईकर्मी,प्रदेश का हर विभाग उबल रहा है। यह किसी एक संगठन की नाराज़गी नहीं,बल्कि सिस्टम पर अविश्वास का विस्फोट है,इतिहास गवाह है कलम बंद करने से सवाल नहीं रुकते, काम बंद कराने से आक्रोश खत्म नहीं होता सरकार के सामने अब दो ही रास्ते हैं बातचीत,भरोसा और समयबद्ध समाधान या फिर एक ऐसा प्रदेश,जहां हर चौक धरनास्थल और हर दिन आंदोलन का दिन हो फैसला सत्ता को करना है।

11 सूत्रीय मांगों पर एकजुटता

धरनास्थल पर वक्ताओं ने लंबित मांगों की अनदेखी पर नाराज़गी जताई। आंदोलन को और व्यापक बनाने की रणनीति तय हुई,कर्मचारियों की एकजुटता,अनुशासन और संगठनात्मक शक्ति स्पष्ट नजर आई।

मनेंद्रगढ़ में कार्रवाई से उबाल

इधर एमसीबी/मनेंद्रगढ़ में हड़ताल के समर्थन पर तीन कर्मचारियों पर शांति भंग के आरोप में कार्रवाई की गई। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश पर सिटी कोतवाली पुलिस कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, कार्रवाई की जद में आए,नगर पंचायत झगराखांड के आरआई संजय पांडेय,खेल अधिकारी गोपाल सिंह और सफाई कर्मी सुरेंद्र प्रसाद जो 29 से 31 दिसंबर तक चल रही हड़ताल के समर्थन में अधिकारियों-कर्मचारियों से संपर्क कर रहे थे।

फेडरेशन का ऐलान...आंदोलन नहीं रुकेगा

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने प्रशासनिक कदम को दमनात्मक प्रयास करार दिया और दो टूक कहा कि किसी भी पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई तो पूरा फेडरेशन उसके साथ खड़ा रहेगा। फेडरेशन ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन पूरी मजबूती से जारी रहेगा।

ट्रिपल राइडिंग पर कोरबा पुलिस की सख्त कार्रवाई करते हुए 96 दोपहिया वाहनों से कुल 42,000 रुपये का अर्थदंड वसूला गया

-संवाददाता-

कोरबा,30 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)।

कोरबा पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात अनुशासन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शहर एवं जिले के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों पर ट्रिपल राइडिंग (तीन सवारी बैठाने) के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, नियम विरुद्ध तीन सवारी बैठाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने एवं आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संचालित किया गया। अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस एवं थाना चौकी स्टाफ द्वारा मुख्यतः शहरी

क्षेत्र के प्रमुख मार्गों,व्यस्त चौराहों व सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग की गई, जिसमें कुल 96 दोपहिया वाहनों पर ट्रिपल राइडिंग करते पाए जाने पर चालान की कार्रवाई की गई। इस अभियान के तहत कटघोरा, बालको और कोटवाली थाना क्षेत्र में अधिकतम 17,13 और 13 वाहनों का चालान किया गया तथा कुल लगभग 42,000 (बयालीस हजार) रुपये का अर्थदंड वसूल किया गया। ऐसे कृत्य न केवल मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन हैं, बल्कि वाहन की संतुलन क्षमता,ब्रेकिंग व नियंत्रण को प्रभावित कर गंभीर दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। कोरबा पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ट्रिपल राइडिंग पर सख्त और निरंतर कार्रवाई की जाएगी तथा बार-बार नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा

ईश्तहार

रा0प्र0क0..... अ- 6 /2024-25

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदिका श्रीमती मीरा सोनकर आ. नरेश राम, उम्र 50 वर्ष, निवासी सत्तीपारा, नेहरू वार्ड क्र. 25 अम्बिकापुर के द्वारा तदाशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदिका के पिता नरेश राम के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर, शीट नं. 02 मोहल्ला-सत्तीपारा स्थित नजूल प्लॉट नं. 630 रकबा 0.02 एकड़ भूमि स्थित है। आवेदिका के पिता / भूधारक नरेश राम की मृत्यु दिनांक 08.04.2019 को हो गई है। अतः भूधारक नरेश राम की मृत्यु हो जाने उपरांत आवेदिका द्वारा उक्त भूमि के नजूल अभिलेख से अपने पिता का नाम विलोपित कर स्वयं सहित अनावेदकगण सत्यनारायण (फौत) के वारिसान श्रीमती हेवन्ती पति स्व. सत्यनारायण, संजू सोनकर,आशीष सोनकर,मनीष सोनकर, मन्जू सोनकर आ.स्व. सत्यनारायण सोनकर,गीता सोनकर,मन्टू सोनकर, त्रिलोकी सोनकर, शम्भू सोनकर, गुड्डू सोनकर आ.स्व. नरेश राम का नाम दर्ज किये जाने हेतु भूधारक मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, मयदस्तावेज सहित आवेदन पत्र, अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 19/01/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा / अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 26/12/2025 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

सार्वजनिक सूचना / इश्तिहार

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मुकेश सिंह पटेल, पिता स्व. प्रदीप कुमार सिंह,उम्र 32 वर्ष,निवासी ग्राम कटकोना, थाना व तहसील पटना, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़) यह सार्वजनिक रूप से घोषित करता हूँ कि मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में मेरे पिता के नाम में त्रुटि दर्ज हो गई है।

मेरे ड्राइविंग लाइसेंस क्रमांक CG16 20120010711 में मेरे पिता का नाम भूलवश प्रदीप कुमार पटेल (Pradeep Kumar Patel) दर्ज हो गया है,जबकि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य शासकीय दस्तावेज़ों में मेरे पिता का सही नाम प्रदीप कुमार सिंह (Pradeep Kumar Singh) दर्ज है।

अतः यह इश्तिहार जनहित में प्रकाशित कराया जा रहा है ताकि संबंधित विभागों एवं आमजन को सूचित किया जा सके कि भविष्य में मेरे सभी शासकीय कार्यों एवं अभिलेखों में मेरे पिता का सही नाम प्रदीप कुमार सिंह (Pradeep Kumar Singh) ही मान्य एवं स्वीकार किया जाए, यह सूचना सत्य एवं मेरे ज्ञान के अनुसार सही है,यदि किसी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस के भीतर लिखित रूप में सूचित कर सकता है। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नाम सुधार की प्रक्रिया को वैध माना जाएगा।

दिनांक-29.12.2025
स्थान- बैकुंठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)

भवदीय,
मुकेश सिंह पटेल
पुत्र - स्व. प्रदीप कुमार सिंह
निवासी ग्राम - कटकोना,जिला कोरिया (छ.ग.)

2025: कोरिया जिला...

उपलब्धियों की चमक, चुनौतियों की छाया और अधूरे वादों का साल

धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मान प्राप्त करती कलेक्टर चंदन त्रिपाठी

संगठन चुनाव की पूरी प्रक्रिया नतीजा यथावत जिलाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता

जिले के इकलौते पटना नगर पंचायत चुनाव में भाजपा का कब्जा

कांग्रेस के लिए 2025: कोरिया जिले में उपलब्धियों से ज्यादा 'कमियों और कमियों' का साल

वर्ष 2025 कोरिया जिले में जहाँ प्रशासन और सत्तारूढ़ दल के लिए उपलब्धियों और राजनीतिक मजबूती का साल रहा,वहीं कांग्रेस के लिहाज से यह वर्ष नुकसान, निराशा और संगठनात्मक कमजोरी का प्रतीक बनकर सामने आया। नगरीय निकायों से लेकर जनपद और जिला स्तर तक हुए लगभग सभी चुनावों में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप पार्टी न सिर्फ सत्ता से दूर रही, बल्कि जनाधार और संगठनदोनों मोर्चों पर कमजोर दिखाई दी,कुल मिलाकर, 2025 कोरिया जिला कांग्रेस के लिए उपलब्धियों का नहीं,बल्कि कमियों और कर्मियों से जुड़ी चुनौतियों का साल रहा। चुनावी हार,कमजोर संगठन और नेतृत्व को लेकर उठते सवालों ने पार्टी की स्थिति को कठिन बना दिया है,अब 2026 कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसा साल साबित हो सकता है–जहाँ या तो पार्टी खुद को नए सिरे से खड़ा करेगी, या फिर राजनीतिक हाशिये की ओर और खिसकती नजर आएगी।

चुनावी मोर्चे पर लगातार हार

2025 में हुए नगरीय निकाय, जनपद पंचायत और जिला पंचायत चुनाव कांग्रेस के लिए शुभ नहीं रहे,अधिकांश नगर पंचायतों में पार्टी को हार मिली, जनपद और जिला पंचायतों में भी कांग्रेस प्रभावी चुनौती पेश नहीं कर सकी,कई परंपरागत कांग्रेस समर्थित क्षेत्रों में भी मतदाताओं का रुझान बदलता नजर आया, इन नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ कमजोर हुई है और संगठन मतदाताओं से जुड़ाव बनाने में असफल रहा।

संगठनात्मक कमजोरी और कार्यकर्ताओं की हताशा

2025 में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या संगठनात्मक शिथिलता रही,बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक सक्रियता की कमी दिखाई दी,कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय का अभाव रहा,कई स्थानों पर चुनाव के दौरान पार्टी की मौजूदगी केवल औपचारिकता तक सीमित दिखी, इसका सीधा असर चुनावी परिणामों पर पड़ा और कार्यकर्ताओं में निराशा व असंतोष गहराता गया।

सड़क सुरक्षा और कानून-व्यवस्थाःचिंता का विषय

2025 सड़क सुरक्षा के लिहाज से कोरिया जिले के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण वर्षों में गिना गया,नेशनल हाईवे और चौरचा,कटगोड़ी जैसे क्षेत्रों में कई भीषण हादसे हुए,जिनमें युवाओं की जान चली गई,हालाँकि प्रशासन ने हेलमेट,सीटबेल्ट और नशे में ड्राइविंग के खिलाफ अभियान चलाया,लेकिन हादसों की संख्या में अपेक्षित कमी नहीं आ सकी, कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर हत्या,आत्महत्या और संदिग्ध मौतों की घटनाओं ने जिले को झकझोर दिया। नशे के खिलाफ आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई जरूर राहत देने वाली रही।

किसान,अतिक्रमण और मानव-वन्यजीव संघर्ष

धान खरीदी में लिमिट,रकबा कटौती और टोकन की समस्या ने किसानों को सबसे ज्यादा परेशान किया। कई केंद्रों पर लंबी कतारें और विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, हाथी-मानव द्वंद में फसलों और घरों को भारी नुकसान हुआ, जबकि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बरसात से पहले कई परिवार बेघर हो गए, जिनके पुनर्वास पर सवाल उठे।

सुशासन,शिक्षा और डिजिटल पहल

सुशासन सप्ताह और सुशासन तिहार के माध्यम से प्रशासन ने गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बनाई,हजारों आवेदनों का समयबद्ध निराकरण हुआ,शिक्षा के क्षेत्र में पीएम श्री स्कूल और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं से छात्रों को लाभ मिला। कलेक्ट्रेट और न्यायालयों में डिजिटलीकरण की शुरुआत को भी एक सकारात्मक कदम माना गया।

राजनीति और पंचायत चुनाव

राजनीतिक दृष्टि से 2025 भाजपा के लिए अनुकूल रहा। पंचायत चुनावों में पार्टी ने जिला, जनपद और नगर पंचायतों में मजबूत पकड़ बनाई। गांवों में नए नेतृत्व के चयन को लेकर उत्साह दिखा, वहीं विपक्ष ने कुछ मुद्दों पर सवाल भी उठाए।

विकास कार्यों की सुस्त रफ्तार

जहाँ एक ओर उपलब्धियों की चर्चा रही,वहीं कई बड़े विकास कार्य अधूरे रहना साल की बड़ी निराशा बना। जिला अस्पताल और एमसीएच भवन,जल जीवन मिशन की अधूरी पाइपलाइनें,प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे घर और सोनहत क्षेत्र के मिनी स्टेडियम जैसे प्रोजेक्ट्स समय-सीमा पार करने के बावजूद पूरे नहीं हो सके। बैकुंठपुर सड़क चौड़ीकरण भी सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहा।

सड़क सुरक्षा और दुःखद घटनाएँ

2025 सड़क सुरक्षा के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहा। नेशनल हाईवे और कुछ प्रमुख मार्ग 'ब्लैक स्पॉट' के रूप में उभरे,जहाँ कई जानलेवा हादसे हुए। इसके अलावा हत्या,आत्महत्या और अन्य आपराधिक घटनाओं ने जिले को झकझोर दिया। प्रशासन ने ट्रैफिक नियमों और नशे के खिलाफ सख्ती जरूर दिखाई,लेकिन हादसों की संख्या चिंता का विषय बनी रही।

2025:कोरिया जिले का साल...जब पहचान बढ़ी, पर भरोसा डगमगाया

उपलब्धियों के बीच उलझा कोरिया,2025 ने क्या सिखाया?

प्रशासनिक प्रयोग बनाम जमीनी हकीकत... कोरिया का 2025

सम्मान से सवालों तकःकोरिया जिले का एक साल

कोरिया 2025:सम्मान भी मिला, सवाल भी खड़े हुए

उम्मीद,उपलब्धि और असंतोष...कोरिया जिले का 2025

कोरिया का 2025:राष्ट्रीय पहचान से स्थानीय नाराज़गी तक

2025 की कहानीःकोरिया में प्रशासन आगे, ज़मीन पीछे

कोरिया 2025:जहाँ तारीफ़ भी रही, तकलीफ़ भी

राष्ट्रीय सम्मान, स्वास्थ्य-सुशासन की उपलब्धियाँ, और साथ में अधूरी योजनाएँ,सड़क हादसे व किसान संकट

विकास के दावे,चुनावी बदलाव और जमीनी चुनौतियों का सालाना लेखा-जोखा

-रवि सिंह-

कोरिया,30 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)।

वर्ष 2025 कोरिया जिले के इतिहास में एक ऐसा साल रहा, जिसे न पूरी तरह उपलब्धियों का कहा जा सकता है और न ही सिर्फ चुनौतियों का, यह वर्ष प्रशासनिक नवाचार, राष्ट्रीय मंच पर पहचान और विकास की नई कोशिशों के साथ-साथ अधूरी योजनाओं, सड़क हादसों और कुछ दुखद घटनाओं के कारण भी याद किया जाएगा। वर्ष 2025 कोरिया जिले के लिए कई मायनों में निर्णायक रहा, यह साल न तो केवल उत्सव का था और न ही केवल असफलताओं का। कहीं राष्ट्रीय मंच पर सम्मान और सराहना मिली, तो कहीं अधूरी योजनाओं, सड़क दुर्घटनाओं और सामाजिक संकटों ने प्रशासनिक दावों की परीक्षा ली, कुल मिलाकर 2025 कोरिया जिले के लिए उपलब्धि और असंतोष का मिला-जुला वर्ष बनकर सामने आया, वर्ष 2025 कोरिया जिले के लिए उपलब्धियों और चुनौतियों का संतुलित मिश्रण रहा,राष्ट्रीय सम्मान, स्वास्थ्य और सुशासन में प्रयोगों ने जिले की छवि को मजबूत किया,लेकिन अधूरे विकास कार्य,सड़क हादसे और सामाजिक समस्याओं ने यह भी साफ किया कि सिर्फ प्रशंसा से जमीनी हकीकत नहीं बदलती, अब 2026 से अपेक्षा यही है कि 2025 में मिली पहचान को ठोस विकास, सुरक्षित सड़कों और समयबद्ध योजनाओं में बदला जाए, ताकि उपलब्धियाँ कागज़ों से निकलकर ज़िंदगी में उतर सकें।

एक नज़र में 2025

क्षेत्र	प्रमुख तथ्य
स्वास्थ्य	चिरायु में 25,000+ बच्चों की जाँच
प्रशासन	सुशासन तिहारः41,000+ आवेदनों का निपटारा
पर्यावरण	जल संरक्षण में राष्ट्रीय सराहना
पर्यटन	टाइगर रिज़र्व ट्रैकिंग की शुरुआत
सड़क सुरक्षा	5 ब्लैक स्पॉट चिन्हित,सख्ती बढ़ी
विकास	कई बड़े प्रोजेक्ट अधूरे

विकास कार्यः दावे ज्यादा,रफ्तार कम...2025 में कोरिया जिले में विकास योजनाओं की सुस्त प्रगति एक बड़ी चुनौती रही

- जिला अस्पताल और एमसीएच भवन
- जल जीवन मिशन की अधूरी पाइपलाइनें
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे मकान
- सोनहत क्षेत्र के मिनी स्टेडियम और सीसी सड़कें

बैकुंठपुर सड़क चौड़ीकरण ये सभी योजनाएँ समय-सीमा पार करने के बावजूद अधूरी रहीं। इससे आम जनता में नाराजगी और प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल बढ़े।

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने पर टीम की सदस्य सोनल राजे के साथ कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ कोरिया

जिला पंचायत चुनाव में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा

कोरिया में कांग्रेस का संगठनात्मक संदेशःबदलाव नहीं,यथास्थिति पर भरोसा

2025 कोरिया जिले में कांग्रेस ने संगठनात्मक मजबूती की बजाय स्थिरता (यथास्थिति) को प्राथमिकता देना ज्यादा जरूरी समझा है,संगठन चुनाव की पूरी प्रक्रिया भले ही औपचारिक रूप से पूरी की गई हो,लेकिन अंततः मोहर फिर से जिलाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता पर ही लगाई गई,यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब जमीनी स्तर पर संगठन की कमजोरी,निष्क्रियता और अपेक्षित जनसंपर्क की कमी को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं, राजनीतिक रूप से यह निर्णय दो संकेत देता है,पहला–प्रदेश नेतृत्व ने यह मान लिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में नेतृत्व परिवर्तन से संगठन को तत्काल कोई लाभ नहीं मिलेगा, दूसरा–यह भी कि संगठन की संभावित कमजोरी की कीमत चुकाने को भी नेतृत्व तैयार है,बशर्ते अंदरूनी असंतोष या शक्ति-संतुलन न बिगड़े,हालांकि आलोचक यह सवाल उठाने से नहीं चूक रहे कि अगर संगठन कमजोर हो रहा है,कार्यकर्ताओं में ऊर्जा की कमी है और चुनावी तैयारी सुस्त है, तो फिर वही नेतृत्व दोहराना किस हद तक व्यावहारिक है? संगठन चुनाव की प्रक्रिया अगर अंततः पूर्वनिर्धारित निर्णय पर ही खत्म होनी थी,तो उसे बदलाव और लोकतांत्रिक अभ्यास का आवरण देने की जरूरत क्यों पड़ी?

महाविद्यालय परिसर में एसपी कार्यालयःविरोध के बावजूद निर्माण

2025 में सबसे ज्यादा विवादित मुद्दों में से एक रहा महाविद्यालय परिसर में एसपी कार्यालय का निर्माण,छात्र संगठनों,शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया, तर्क दिया गया कि शैक्षणिक परिसर की गरिमा और स्वायत्तता प्रभावित होगी,इसके बावजूद,तमाम विरोध और ज्ञापनों के बाद भी अंततः महाविद्यालय परिसर में ही एसपी कार्यालय का निर्माण शुरू कर दिया गया,यह निर्णय प्रशासनिक दृष्टि से भले जरूरी बताया गया हो, लेकिन इससे यह सवाल गहराया कि क्या जनभावनाओं और शिक्षा के हितों को नजरअंदाज किया गया?

राष्ट्रीय मंच पर कोरिया की पहचान

2025 में कोरिया जिले ने प्रशासनिक क्षमता और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के कारण देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई, जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं,शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी विस्तार के चलते धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में जिले को राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ,यह सम्मान न केवल जिला प्रशासन की कार्यशैली का प्रमाण बना,बल्कि आदिवासी अंचलों में भरोसे की वापसी का भी संकेत माना गया, इसी तरह कुपोषण प्रबंधन में जिले को नीति आयोग की राष्ट्रीय रैंकिंग में तीसरा स्थान मिला,यह उपलब्धि आंगनबाड़ी,स्वास्थ्य अमला और प्रशासनिक निगरानी की संयुक्त मेहनत का परिणाम रही,जल संरक्षण के क्षेत्र में भी अमृत सरोवर,तालाब पुनर्जीवन और जनभागीदारी आधारित प्रयासों को राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में सराहा गया,स्वास्थ्य क्षेत्र में चिरायु योजना के तहत 25 हजार से अधिक बच्चों की जांच और निःशुल्क उपचार ने जिले को राज्य स्तर पर पहचान दिलाई।

राष्ट्रीय पहचान और सम्मान

जनजातीय कल्याण में उत्कृष्टता: अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में द्रौपदी मुर्मू के हाथों कोरिया जिले को 'धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान' के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु सम्मान मिला। यह सम्मान कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने प्राप्त किया।

नीति आयोग की सराहना: कुपोषण प्रबंधन में नवाचारों के लिए नीति आयोग के यूज़-केस चैलेंज में जिले को देश में तीसरा स्थान मिला।

पर्यावरण व जल संरक्षण: छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में अमृत सरोवर,वर्षा जल संचयन और जनभागीदारी के प्रयासों की सराहना हुई।

विकास की रफ्तार

अधूरे प्रोजेक्ट्स– जिला अस्पताल/एमसीएचः डेडलाइन पार; फिनिशिंग में देरी–पूरी शुरुआत 2026-27 तक खिसकने की आशंका।

जल जीवन मिशन: पाइपलाइन बिछी, पर कई गाँवों में नल सूखे–टंकी/कनेक्टिविटी अधूरी।

प्रधानमंत्री आवास (सोनहत): सैकड़ों मकान छत/लिंटर पर अटके।

मिनी स्टेडियम/सीसी सड़कें (सोनहत): स्वीकृति के बाद काम ठप्प।

बैकुंठपुर सड़क चौड़ीकरण: वादे बहुत, प्रगति शून्य।

उच्च शिक्षा: पीजी कॉलेज अनियमितताओं पर जाँच ठंडी; कॉलेज परिसर में एसपी कार्यालय को लेकर विरोध के बीच निर्माण शुरू।

पर्यटन और पर्यावरण

गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ट्रैकिंग की शुरुआत से पर्यटन संभावनाएँ बढ़ीं।

चुनौतियाँ: राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में अनियमितताओं की चर्चाएँ और मानव-वन्यजीव संघर्ष–विशेषकर हाथी-मानव द्वंद में फसल/आवास क्षति।

कानून-व्यवस्था और सामाजिक घटनाएँ

दुःखद वारदातें: जमगहना क्षेत्र में हत्या-आत्महत्या की घटना; युवक-युवती के फाँसी पर मिले शव–क्षेत्र में सनसनी।

नशे पर प्रहार: आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाइयाँ; सप्लायरों पर शिकंजा।

स्कूल सुरक्षा: ओवरलोड वैनों पर सख्त कार्रवाई।

सड़क सुरक्षाःचुनौतीपूर्ण वर्ष

ब्लैक स्पॉट्सःएनएच-43, चौरचा,कटगोड़ी मोड़–तेज रफ्तार और लापरवाही से कई जानें गईं।

प्रमुख हादसे

चौरचा-बैकुंठपुर मार्ग पर हाइवा-बाइक टक्कर–तीन युवकों की मौत; सड़क सुधार की माँग।

बरसात में बस पलटी–15+ घायल,राहत कार्य तत्पर।

प्रशासनिक कदमःहेलमेट-सीटबेल्ट अभियान, शराब पीकर वाहन चलाने पर जुर्माना, संवेदनशील वन क्षेत्रों में स्पीड-लिमिट/सावधानी बोर्ड।

कृषि और आजीविका

धान खरीदीःरकबा-कटौती, लिमिट और टोकन समस्याएँ–किसान परेशान; विरोध प्रदर्शन।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई: बरसात पूर्व कई परिवार बेघर–पुनर्वास की मांग।

स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि

स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से 2025 कोरिया के लिए सकारात्मक रहा, चिरायु योजना के अंतर्गत जिले में 25 हजार से अधिक बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई। निःशुल्क बाल हृदय रोग शिविरों के माध्यम से कई गंभीर रूप से बीमार बच्चों को नया जीवन मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों की निरंतरता ने प्रशासन को राज्य स्तर पर प्रशंसा दिलाई, हालाँकि, दूसरी ओर नया जिला अस्पताल और एमसीएच भवन अब भी अधूरे रहे। भवन तैयार होने के बावजूद फिनिशिंग और संसाधनों की कमी के कारण आमजन को अब भी पुराने अस्पताल ढांचे पर निर्भर रहना पड़ा, जिससे प्रशासनिक उपलब्धियों पर सवाल भी खड़े हुए।

सुशासन,शिक्षा और डिजिटल पहल

वर्ष 2025 में सुशासन तिहार और सुशासन सप्ताह के जरिए प्रशासन जनता के सीधे संपर्क में दिखा, जिले भर से 40 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए,जिनके निराकरण का दावा प्रशासन ने समयबद्ध रूप से किया, 'सुशासन ऑन व्हील्स' और 'सुशासन संगवारी' जैसी पहलें दूरस्थ और बुजुर्ग आबादी तक पहुंचने में कारगर रहीं, शिक्षा के क्षेत्र में पीएम श्री स्कूल और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजनाओं से छात्रों को नई सुविधाएं और अवसर मिले। कलेक्ट्रेट और न्यायालयों में डिजिटलीकरण की शुरुआत को भी प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम माना गया।

जिला मुख्यालय सड़क चौड़ीकरणःवादों की फाइल,काम शून्य

बैकुण्ठपुर जिला मुख्यालय की मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण 2025 का सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा रहा,हर कुछ महीनों में इस पर नई तारीख,नया आश्वासन और नई घोषणा सामने आती रही, लेकिन साल के अंत तक काम शुरू होना तो दूर,ठोस कार्ययोजना तक नजर नहीं आई,ट्रैफिक जाम, संकरी सड़कें और बढ़ते हादसे,व्यापारियों और आम नागरिकों की लगातार शिकायतें, जनप्रतिनिधियों के स्तर पर सिर्फ बैठकें और बयान, 2025 में यह साफ हो गया कि सड़क चौड़ीकरण का मामला घोषणाओं की राजनीति में ही उलझा रहा।

पीजी कॉलेज बैकुण्ठपुरःअनियमितताओं पर जांच सिफर

बैकुण्ठपुर पीजी कॉलेज में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का मुद्दा पूरे साल सुर्खियों में रहा,छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों ने बार-बार जांच की मांग उठाई,लेकिन न कोई स्वतंत्र जांच समिति बनी,न किसी जिम्मेदार पर कार्रवाई हुई,न ही प्रशासन की ओर से ठोस जवाब सामने आया, परिणामस्वरूप,यह मामला भी फाइलों में दबा एक और प्रकरण बनकर रह गया, जिसने शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए।

राजनीतिःपंचायत चुनावों में भाजपा का दबदबा

राजनीतिक दृष्टि से 2025 भाजपा के लिए मजबूत साबित हुआ,पंचायत चुनावों में जिला,जनपद और नगर पंचायतों में भाजपा ने एकतरफा जीत दर्ज की। गांवों में नए नेतृत्व को लेकर उत्साह दिखा,वहीं विपक्ष ने विकास कार्यों की धीमी गति और किसानों की समस्याओं को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की।

विपक्ष की भूमिका भी कमजोर

2025 में कांग्रेस विपक्ष के रूप में भी अपेक्षित दबाव नहीं बना सकी, धान खरीदी,अधूरे विकास कार्य,सड़क हादसे और प्रशासनिक मुद्दों पर आवाज जरूर उठी,लेकिन वह न तो व्यापक जनआंदोलन बन सकी और न ही राजनीतिक लाभ में बदल पाई,इससे यह संदेश गया कि कांग्रेस मुद्दे तो उठा रही है, लेकिन उन्हें धार देने और जनता से जोड़ने में चूक रही है।

2026 की राहःसवाल और संभावनाएँ...

अब सबसे बड़ा सवाल यही है 2026 कांग्रेस के लिए कैसा होगा? क्या पार्टी संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करेगी? नेतृत्व में बदलाव या स्पष्टता लाएगी? जमीनी कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय कर पाएगी? या फिर 2025 की तरह 2026 भी आत्ममंथन और अंदरूनी खींचतान में ही निकल जाएगा–यह तो आने वाला साल ही बताएगा।

जिलाध्यक्ष का मुद्दा बना चर्चा का केंद्र

पूरा साल कांग्रेस जिला अध्यक्ष का विषय पार्टी के भीतर चर्चा और असंतोष का कारण बना रहा,नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही,संगठनात्मक फैसलों में स्पष्टता और आक्रामकता की कमी महसूस की गई,कई वरिष्ठ नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं में यह धारणा बनी कि नेतृत्व बदलाव या पुनर्गठन की जरूरत है,इस आंतरिक खींचतान ने कांग्रेस को एकजुट होकर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ प्रभावी भूमिका निभाने से रोके रखा।

CMYK

प्रदेश की संक्षिप्त खबरें...

साल की अंतिम साय कैबिनेट की बैठक आज

रायपुर,30 दिसम्बर 2025(ए)। छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिपरिषद् की महत्वपूर्ण बैठक 31 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। यह बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पूर्वान्ह 11.30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय,महानदी भवन में संपन्न होगी। वर्ष के अंतिम दिन होने जा रही इस कैबिनेट बैठक को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में खासा महत्व देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। आगामी योजनाओं,विकास कार्यों,प्रशासनिक निर्णयों और जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद् की मुहर लग सकती है। इसके अलावा नए वर्ष 2026 की शुरुआत से पहले कुछ नीतिगत फैसलों को अंतिम रूप दिए जाने की भी संभावना जताई जा रही है।

कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे, जिन पर विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय लिए जाएंगे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा विभागीय कार्यों की समीक्षा किए जाने के साथ-साथ लंबित मामलों पर भी दिशा-निर्देश दिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि बैठक में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, उद्योग और बुनियादी ढांचे से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श हो सकता है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में बैठक को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहेंगे। सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर भी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। राज्य सरकार के लिए यह बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार वर्ष 2025 के कार्यों की समीक्षा और आगामी वर्ष की प्राथमिकताओं को तय कर सकती है। बैठक के बाद लिए गए निर्णयों की जानकारी आधिकारिक विज्ञप्ति के माध्यम से साझा की जाएगी।

विधायक की पत्नी लहूलुहान हालत में मिली

हत्या की कोशिश से सनसनी

बस्तर,30 दिसम्बर 2025(ए)। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल की पत्नी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया है। हमले में उनके दोनों हाथों की नसें कट गई हैं, जबकि गले पर भी चोट के गहरे निशान पाए गए हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, घटना के बाद आज सुबह करीब 8 बजे उन्हें महारानी अस्पताल लाया गया। उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने तत्काल उन्हें आईसीयू में भर्ती किया। स्थिति गंभीर बनी हुई है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी

कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। अस्पताल परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सके। पुलिस सभी संभावित एंगल से मामले की जांच कर रही है और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आत्मीय स्वागत

रायपुर,30 दिसम्बर 2025(ए)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जशपुर आगमन पर आगडीह हवाई पट्टी में राज्यपाल रमेन डेका,झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार,मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य मंत्रियों,जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। विष्णुदेव साय का ट्वीट - मधेश्वर महादेव की पावन भूमि, गौरवशाली संस्कृति और अनुपम नैसर्गिक सौंदर्य से समृद्ध जशपुर की धरती पर माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपका आगमन जशपुर के लिए गौरव और प्रेरणा का अविस्मरणीय क्षण है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया,जिसने हर किसी के दिल को जीत लिया। दरअसल, राष्ट्रपति सोमवार को एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह से लौट रहीं थीं। इस दौरान,

राष्ट्रपति ने तोड़ा नियम

नियमों के अनुसार,पूरे रूट में राष्ट्रपति का काफिला कहीं भी नहीं रुकता,लेकिन बच्चों की मासूमियत ने राष्ट्रपति का काफिला रुकवा दिया। काफिला जैसे ही रुका,वैसे ही सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हो गए। राष्ट्रपति उत्साह के साथ गाड़ी से उतरीं और सीधे बच्चों और महिलाओं के पास पहुंच गईं।

राष्ट्रपति का काफिला जब आकाशवाणी चौक से गुजर रहा था तो सड़क किनारे कुछ बच्चे खड़े थे। वे राष्ट्रपति को देखने के लिए उत्साहित थे, जिसे देखते हुए उन्होंने अपना काफिला रुकवा दिया।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चला ईडी का 'हंटर'

- 38 करोड़ की ये संपतियां कुर्क
- कैसे हुआ था लूट का 'पार्ट-बी' खेल

रायपुर,30 दिसम्बर 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। 31 आबकारी अधिकारियों की करीब 38.21 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। ईडी के इस एक्शन में तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास भी घेरे में आए हैं। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई है।

ईडी की जांच में सामने आया है कि इस घोटाले से राज्य सरकार को 2 हजार 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जांच एजेंसी के मुताबिक, आबकारी विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों ने मिलकर पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया और एक समानांतर अवैध व्यवस्था चला दी।

शराब घोटाले पर ईडी का खुलासा

ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास और सीएसएमसीएल के तत्कालीन एमडी अरुणपति त्रिपाठी ने मिलकर एक पार्ट-बी योजना चलाई. इसके तहत सरकारी शराब दुकानों के जरिए बिना हिसाब-किताब की देशी शराब बेची गई। इस अवैध शराब करोबार के लिए डुप्लीकेट होलोग्राम इस्तेमाल किए गए।

अफसरों को मिलता था कमीशन

शराब की बोतलें और खेप सरकारी रिकॉर्ड से बाहर रखी गईं. शराब को सीधे डिस्टिलरी से दुकानों तक पहुंचाया गया, जिससे सरकारी गोदामों को बायपास किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि आबकारी अधिकारियों को अपने-अपने इलाकों में पार्ट-बी शराब बिकवाने के बदले प्रति केस 140 रुपये का कमीशन दिया जाता था। ईडी के अनुसार, निरंजन दास ने अकेले 18 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध कमाई की और उन्हें हर महीने करीब 50 लाख रुपये की रिश्वत मिलती थी। कुल मिलाकर 31 आबकारी अधिकारियों ने 89.56 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) हासिल की

ईडी ने जिन संपत्तियों को कुर्क किया है,उनमें 21.64 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। इसमें कुल 78 संपत्तियां, जिनमें लग्जरी बंगले,महंगे फ्लैट,कमर्शियल दुकानें और कृषि भूमि शामिल हैं. 16.56 करोड़ रुपये की चल संपत्ति- 197 मदों में फिक्स्ड डिपॉजिट,कई बैंक खातों की रकम, बीमा पॉलिसियां, शेयर और म्यूचुअल फंड शामिल हैं।

नकली नोटों का बड़ा खुलासा,पति-पत्नी गिरफ्तार

दुर्ग,30 दिसम्बर 2025 (ए)। जिले के रानीतराई साप्ताहिक बाजार में नकली नोट चलाने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नकली नोट चलाने वाले आरोपी अरूण कुमार तुरंग और उसकी पत्नी राखी तुरंग को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों के पास से 500, 200 और 100 रुपये के कुल 1 लाख 70 हजार 500 रुपये के नकली नोट, साथ ही कलर फोटो कॉपी प्रिंटर और कागज बरामद किए गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 29 दिसंबर 2025 को थाना रानीतराई क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों द्वारा नकली नोट चलने की सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच के दौरान सब्जी विक्रेता तुलेश्वर सोनकर ने शिकायत दर्ज कराई कि एक पुरुष और महिला ने उससे 60 रुपये का सामान खरीदा और 500 रुपये का नोट दिया। बाद में बाजार में नकली नोट चलने की चर्चा होने पर जब उसने नोट की जांच की तो वह जाली निकला। जांच में सामने आया कि आरोपी दंपति ने न केवल तुलेश्वर सोनकर बल्कि रानीतराई बाजार के कई अन्य व्यापारियों- भावेश देवागंन, आदोराम बेलवाकुदा, दीपक साहू, संतोष देवागंन, शीतल यादव, चंद्रिका बाई, रोहित सोनकर और भूपेंद्र पटेल को भी नकली नोट देकर सामान खरीदा था।

कलम बंद-काम बंद आंदोलन का जबरदस्त असर

पूरे प्रदेश में सरकारी कामकाज ठप्प

रायपुर,30 दिसम्बर 2025(ए)। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा प्रदेशभर में कर्मचारियों के हितों से जुड़ी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन का आज व्यापक असर देखने को मिला। फेडरेशन की कलम बंदङ्काम बंद हड़ताल के चलते इंद्रावती भवन सहित अनेक शासकीय कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा और अधिकांश स्कूलों में ताले लटके दिखाई दिए। नगरीय निकायों के कर्मचारियों ने अवकाश लेकर प्रदर्शन में भाग लिया, वहीं विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मचारियों ने भी अवकाश लेकर आंदोलन का समर्थन किया। नवा रायपुर स्थित विभागाध्यक्ष, निगम,बोर्ड आदि कार्यालयों में भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कलम बंद रखकर आंदोलन का समर्थन किया, जिसके कारण वरिष्ठ अधिकारियों के लिए नवा रायपुर स्थित शासकीय कार्यालयों तक पहुंचना भी कठिन हो गया।

फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा एवं संभाग प्रभारी चंद्रशेखर तिवारी के मार्गदर्शन में रायपुर में आयोजित आंदोलन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। जिला संयोजक पीतांबर पटेल, नवा रायपुर विभागाध्यक्ष कार्यालय के अध्यक्ष जयकुमार साहू एवं नवा रायपुर संयोजक संतोष कुमार वर्मा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में नारा लगाया। महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद और बलौदाबाजार में भी संबंधित जिला संयोजकों टेकराम सेन, चंदूलाल चंद्राकर, एम. आर. खान और एल. एस. ध्रुव के नेतृत्व में ÷अब नई सहिबो, मोदी के गारंटी लेकर रहीबो÷ जैसे नारों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया गया।

आंदोलन में सभी जिलों के कर्मचारियों और शिक्षकों ने अवकाश लेकर सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। इसी तरह दुर्ग संभाग में संभाग प्रभारी राजेश चटर्जी के मार्गदर्शन में और जिला संयोजक विजय लहरे के नेतृत्व में कलम बंदङ्काम बंद आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला। राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम और मानपुरङ्क मोहला में क्रमशः जिला संयोजक सतीश व्यौहारे, लोकेश साहू, अश्वनी बनर्जी, अर्जुन चंद्रवंशी और ओ. पी. माहला के नेतृत्व में रैलियां निकाली गईं और कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए।

बिलासपुर संभाग में संभाग प्रभारी जी. आर. चंद्रा और रोहित तिवारी के मार्गदर्शन में तथा जिला संयोजक डॉ. बी. पी. सोनी के नेतृत्व में हुए आंदोलन में कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। जांजगीरङ्कचांपा, कोरबा, मुंगेली, गौरेलाङ्कपेंड्राङ्कमरवाही, रायगढ़ और सारंगढ़ङ्कबिलाईगढ़ जिलों में भी जिला संयोजकों विश्वनाथ परिहार, के. आर. डहरिया, जे. एस. ध्रुव, डॉ. संजय शर्मा, आशीष रंगारी और फकीरा यादव के नेतृत्व में उग्र प्रदर्शन हुए और बड़ी संख्या में कर्मचारियों एवं शिक्षकों ने अवकाश लेकर भागीदारी की। बस्तर संभाग में संभाग प्रभारी कैलाश चौहान और टार्जन गुप्ता के मार्गदर्शन में तथा जिला संयोजक गजेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में जगदलपुर में जबरदस्त उत्साह के साथ आंदोलन हुआ। कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में भी जिला संयोजकों प्रमोद तिवारी, शिवराज सिंह ठाकुर, डॉ. दीपेश रावतें, के. डी. राव, अरविंद यादव और विनायक साहू के नेतृत्व में रैलियां और धरने आयोजित किए गए।

इसी प्रकार सरगुजा संभाग में संभाग प्रभारी ओंकार सिंह और नृपेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में अंबिकापुर के जिला संयोजक कमलेश सोनी के नेतृत्व में कर्मचारियों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, जशपुर और मनेंद्रगढ़ङ्कचिरमिरीङ्क भरतपुर जिलों में भी संबंधित जिला संयोजकों डॉ. आर. एस. सिंह, डॉ. आर. एस. चांदे, डॉ. दीपेश रावटे, संतोष कुमार तांडे और गोपाल सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपे और नारे लगाए। फेडरेशन द्वारा घोषित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की जमीन तैयार हो चुकी है। 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक घोषित काम बंदङ्ककलम बंद आंदोलन को प्रदेशभर में व्यापक समर्थन मिल रहा है। फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि सरकार शीघ्र ही सार्थक संवाद प्रारंभ नहीं करती, तो फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान करने के लिए बाध्य होगा।

फेडरेशन की प्रमुख मांगों में केंद्र सरकार के समान कर्मचारियों एवं पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता लागू करना, डीए एरियर्स की राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में समायोजित करना, सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान प्रदान करना, विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने हेतु पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करना, शिक्षकों की सेवा गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से मानकर समस्त सेवा लाभ देना, सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान देना, अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10 प्रतिशत सीलिंग में शिथिलीकरण, प्रदेश में कैशलेस उपचार सुविधा लागू करना, पंचायत सचिवों का शासकीयकरण, अर्जित अवकाश के नगदीकरण की सीमा 300 दिवस करना, दैनिक, अनियमित एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की ठोस नीति बनाना तथा सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने जैसी मांगें शामिल हैं। प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला संयोजकों एवं कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा है और आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि फेडरेशन संवाद और समाधान चाहता है, लेकिन यदि सरकार चुप्पी साधे रहती है, तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन और अधिक तीव्र किया जाएगा।

बघेल ने फिर साधा निशाना

कहा...धर्म का चोला पहनकर चंदा वसूली करने वाले ये लोग भाजपा के एजेंट...

बिलासपुर,30 दिसम्बर 2025(ए)। कथावाचकों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर फिर हमला बोला है। लिंगियाडीह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बघेल ने धीरेंद्र शास्त्री और पं. प्रदीप मिश्रा पर निशाना साधते हुए उन्हें धर्म का चोला पहनकर चंदा वसूली करने वाला बताया। बघेल ने कहा कि यदि कथावाचन और धार्मिक आयोजन वास्तव में जनकल्याण के लिए हैं, तो चंदा लेना बंद किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कथावाचक अंधविश्वास फैलाकर आस्था का व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कथाओं और दिव्य दावों से हर समस्या का समाधान संभव है, तो फिर चंदा क्यों लिया जा रहा है?

डिप्टी सीएम अरुण साव द्वारा कांग्रेस को सनातन विरोधी बताए जाने पर बघेल ने तंज कसा कि उन्होंने सनातन धर्म का ठेका कब और कैसे लिया गया? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार धार्मिक आयोजनों को संरक्षण देकर आस्था को राजनीतिक हथियार बना रही है। बघेल ने एक प्रतीकात्मक कहानी सुनाते हुए कहा कि जंगल में बंदर को राजा बना दिया गया,जो संकट के वक्त बस इधर-उधर कूदता रहा। उनका इशारा डिप्टी सीएम की कार्यशैली पर था। साथ ही बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए अब वे घर बैठ गए हैं और संतरी की भूमिका में हैं।

लिंगियाडीह के आंदोलन में हुए शामिल

बिलासपुर पहुंचे बघेल लिंगियाडीह में मकान तोड़ने के विरोध में चल रहे आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 38 दिनों से धरना-प्रदर्शन जारी है, फिर भी सरकार गरीबों पर तुगलकी फैसले थोप रही है। उन्होंने सवाल किया कि 80 फीट सड़क बनने के बाद भी तोड़फोड़ क्यों की जा रही है? पूर्व मंत्री बी.आर. यादव के समय दिए गए पट्टों की अनदेखी कर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है

बघेल ने दो टूक कहा कि कांग्रेस गरीब-विरोधी फैसलों के खिलाफ सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी और बस्तियों को उजड़ने नहीं देगी।

छाती के दुर्लभ कैंसर का सफल ऑपरेशन

अंबेडकर अस्पताल में बची मरीज की जान

रायपुर,30 दिसम्बर 2025(ए)। पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के कैंसर सर्जरी विभाग ने चिकित्सा क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। कैंसर सर्जरी विभाग की टीम ने छाती के एक दुर्लभ एवं जटिल कैंसर मेडियास्टाइनल जर्म सेल ट्यूमर का सफल ऑपरेशन कर एक बार फिर एक 29 वर्षीय पुरुष मरीज की जान बचाई। मरीज छाती में गांठ, सांस लेने में तकलीफ और लगातार दर्द की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचा था।कैंसर सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. आशुतोष गुप्ता ने केस की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ङ्कपूर्व में मरीज का उपचार एम्स रायपुर के कैंसर विभाग में चल रहा था, जहां बायोप्सी जांच में मेडियास्टाइनल जर्म सेल ट्यूमर की पुष्टि हुई। प्रारंभिक जांच में

छाती के बीच स्थित गांठ का आकार लगभग 13×18×16 सेंटीमीटर पाया गया, जो हृदय के समीप बड़ी रक्त नलियों से चिपकी हुई थी। उच्च जोखिम को देखते हुए एम्स रायपुर के चिकित्सकों ने पहले कीमोथेरेपी देने का निर्णय लिया।जनवरी 2025 से जून 2025 तक मरीज को छह चक्र (cycle) कीमोथेरेपी दी गई, जिससे गांठ का आकार घटकर 4×3×4 सेंटीमीटर रह गया। इसके बाद मरीज को एम्स रायपुर से रेफर कर डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के कैंसर सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. आशुतोष गुप्ता के पास भेजा गया।

डॉ. गुप्ता ने सभी जांच रिपोर्टों का गहन परीक्षण करने के बाद सर्जरी का निर्णय लिया। गांठ की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए हृदय सर्जरी विभागाध्यक्ष से परामर्श लिया गया तथा निश्चेतना विभाग से सर्जरी की फिटनेस प्राप्त की गई। लगभग 3 से 4 घंटे तक चली इस जटिल सर्जरी में गांठ को बाएं फेफड़े के एक हिस्से सहित अत्यंत निपुणता से निकाला गया।

सर्जरी पूरी तरह सफल रही और मरीज को कुछ दिनों के उपचार के बाद स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उपचार के बाद मरीज समय- समय पर फॉलोअप के लिए चिकित्सालय आ रहा है। इस जटिल ऑपरेशन में डॉ. आशुतोष गुप्ता, डॉ. के. के. साहू, डॉ. किशन सोनी, डॉ. गुंजन अग्रवाल, डॉ. सुश्रुत अग्रवाल, डॉ. समृद्ध, डॉ. लावण्या, डॉ. सोनम एवं डॉ. अनिल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

डिजिटल अरेस्ट के जरिए 57 लाख की साइबर ठगी

अंतर्राज्यीय ठग को पुलिस ने यूपी से किया गिरफ्तार

बिलासपुर,30 दिसम्बर 2025 (ए)। रेंज साइबर थाना बिलासपुर को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही बड़ी साइबर ठगी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। साइबर थाना टीम ने भय दिखाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर वर्चुअल नंबर, फर्जी सिम कार्ड और फर्जी बैंक खातों के माध्यम से 57 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप है। मिली जानकारी के अनुसार थाना सिविल लाइन बिलासपुर से जांच हेतु प्राप्त अपराध क्रमांक 883/25 धारा 318(4),309 बीएनएस एवं आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।

फर्जी केस से बचाने के नाम पर की ठगी

इस मामले में प्रार्थी को अज्ञात आरोपियों द्वारा वर्चुअल मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल कर मनी लॉन्ड्रिंग केस में संलिप्त होने का डर दिखाया गया। केस से बचाने के नाम पर डिजिटल अरेस्ट कर पीड़ित से कुल 57 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए।

जांच में खुला खातों का कनेक्शन

विवेचना के दौरान साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से अद्यतन जानकारी, बैंक खातों का विवरण, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए। जांच में आरोपियों के बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) और दिल्ली क्षेत्र से जुड़े होने के संकेत मिले। पुलिस महानिरीक्षक रेंज बिलासपुर डॉ. संजीव शुक्ला एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर निरीक्षक गोपाल सतपथी के नेतृत्व में विशेष टीम दिल्ली रवाना की गई। लगातार तीन दिन की पतासाजी के बाद टीम ने मनिंदर सिंह 54 वर्ष निवासी शिकारपुर, जिला बुलंदशहर को स्थानीय पुलिस के सहयोग से तलब कर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करना स्वीकार किया।

लेगेसी लोन नामक ऐप का किया इस्तेमाल

आरोपी मनिंदर सिंह फर्जी सिम, वर्चुअल नंबर और बैंक खातों का उपयोग कर ठगी की राशि सोशल मीडिया पर प्रचारित ÷लेगेसी लोन÷ नामक ऐप के माध्यम से आहरण करता था। वह कमीशन के लालच में अपनी फर्म ÷शिकारपुरिहा रियालिटी प्रा.लि.÷ के करंट अकाउंट में ठगी की रकम मंगवाकर निकालता था। इस कार्रवाई में उप पुलिस अधीक्षक निमितेश सिंह के मार्गदर्शन में साइबर थाना टीम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही।

CMYK

2025 छत्तीसगढ़ : फाइलें दौड़ती रहीं, जनता खड़ी रही...

फाइलों में विकास, जमीन पर सवाल... प्रशासन चला, भरोसा डगमगाया

2025 : आदेशों का साल, अनुभवों की कमी, छत्तीसगढ़ की 2025 डायरी : फैसले बहुत, राहत कम

2025 : छत्तीसगढ़ में शासन था, अनुभूति नहीं...जनता लाइन में...सिस्टम फाइल में...

2025 : छत्तीसगढ़ प्रशासन की परीक्षा का साल, सिस्टम मजबूत, सेवा कमजोर, मिशन मोड या भ्रम मोड?

2025 का लेखा-जोखा : छत्तीसगढ़ में शासन बनाम जमीनी सच्चाई,उपलब्धियों के बीच अनुत्तरित सवाल,एक साल,कई तस्वीरें

2025 चेतावनी था, 2026 इम्तिहान होगा...अगर यही चला, तो आगे क्या?

2025 के सबक : क्या 2026 में प्रशासन बदलेगा?

-न्यूज डेस्क-

रायपुर,30 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)। 2025 छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए निर्णयों का साल नहीं, आदेशों का साल रहा, साल भर शासन-प्रशासन यह साबित करता रहा कि फाइलें तेज चल सकती हैं,लेकिन जनसेवा वहीं ठहरी रही जहाँ नेटवर्क नहीं, सड़क नहीं और जवाबदेही नहीं, प्रशासन का चेहरा मिशन मोड बताया गया, पर जमीन पर यह प्रोटोकॉल मोड बनकर रह गया, नक्सल उन्मूलन के नाम पर प्रशासन को सुरक्षा ढांचे में ऐसा बाँध दिया गया कि कलेक्टर जनप्रतिनिधि नहीं,कोऑर्डिनेटर बन गए विभाग सेवक नहीं, रिपोर्टर बन गए डिजिटल प्रशासन के दावे 2025 में सबसे ज्यादा बेनकाब हुए, छात्रवृत्ति के लिए पहाड़ चढ़ते छात्र, पेंशन के लिए भटकते बुजुर्ग,और प्रमाण-पत्र के लिए लाइन में खड़े नागरिक यह सब उस सिस्टम की तस्वीर है जो ऑनलाइन तो है,पर ऑन-ग्राउंड नहीं,भ्रष्टाचार के मामलों में प्रशासन की नीति और भी विचित्र रही,छोटे कर्मचारी पकड़ में आए, बड़े हस्ताक्षर 'जांचाधीन' रह गए, यही कारण है कि 2025 में भय नहीं, भ्रम का प्रशासन दिखा, 2025 में प्रशासन ने यह साबित किया कि सिस्टम चल सकता है लेकिन जनता के साथ नहीं, जनता के ऊपर।

प्रशासनिक दृष्टि से 2025 छत्तीसगढ़ के लिए कैसा रहा?

1. प्रशासन पर सुरक्षा का भारी दबाव

- पूरा साल नक्सल प्रभावित जिलों (बीजापुर,सुकमा, दंतेवाड़ा,नारायणपुर) में प्रशासन सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल में रहा
- कई बार कलेक्टर-एसपी का निर्णय क्षेत्रीय हालात से बंधा दिखा...
- 'विकास' की फाइलें भी 'सुरक्षा क्लियरेंस' के बाद ही आगे बढ़ीं...
- नतीजाः प्रशासन सक्रिय रहा,लेकिन स्वतंत्र निर्णय क्षमता सीमित दिखी...

2. ट्रांसफर-पोस्टिंग और अस्थिरता

- 2025 में आईएएस / आईपीएसी / जिला स्तर पर असामान्य रूप से ज़्यादा बदलाव
- कई जिलों में अधिकारी पूरे साल 'सेट' ही नहीं हो पाए...
- योजनाओं की निरंतरता प्रभावित हुई...
- संदेश साफ़ थाः 'परफॉर्मेंस से ज़्यादा भरोसे' का प्रशासन...

3. भ्रष्टाचार पर कार्रवाईः दिखी, पर चयनात्मक

- एसीबी/ ईओडब्ल्यू की कार्रवाइयाँ हुईं...
- सहकारी विभाग, शिक्षा, बैंकिंग, भर्ती और पंचायत स्तर पर मामले सामने आए...
- लेकिन बड़े नामों तक कार्रवाई नहीं पहुँची...
- प्रशासन पर आरोप लगाः छोटे कर्मचारी पकड़े गए, सिस्टम बच गया...

4. डिजिटल प्रशासन की पोल

- छात्रवृत्ति, पेंशन, धान खरीदी, जाति-निवास प्रमाण-पत्र...
- ऑनलाइन सिस्टम की विफलता...
- नेटवर्क और सर्वर के नाम पर आम जनता परेशान
- 2025 ने साबित कियाः डिजिटल सिस्टम है, लेकिन डिजिटल क्षमता नहीं...

5. जमीनी निरीक्षण बनाम कागजी रिपोर्ट

- कई योजनाएँ फाइलों में 100%
- जमीन पर 50% भी नहीं

कलेक्टर स्तर पर निरीक्षण कम,रिपोर्टिंग ज़्यादा

प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक घटना - 2025- नक्सल उन्मूलन को प्रशासनिक मिशन घोषित करना, यह केवल सुरक्षा फैसला नहीं था यह पूरे प्रशासनिक ढांचे की दिशा बदलने वाला निर्णय था। क्यों यह सबसे बड़ी प्रशासनिक घटना मानी गई? पहली बार:कलेक्टर,वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी को नक्सल उन्मूलन से सीधे जोड़ा गया, 'सामान्य प्रशासन'? 'मिशन मोड प्रशासन ', अबूझमाड़, अंदरूनी इलाकों में सड़क, पुल, स्कूल, मोबाइल टावर प्रशासनिक आदेश से, सुरक्षा कवच में यह फैसला आने वाले 10 वर्षों के प्रशासनिक मॉडल को प्रभावित करेगा।

संक्षिप्त निष्कर्ष	पहलूस्थिति
प्रशासनिक स्थिरता	कमजोर
सुरक्षा समन्वय	मजबूत
भ्रष्टाचार नियंत्रण	अधूरा
सेवा वितरण	असंतोषजनक
निर्णय की स्पष्टता	थी,पर कठोर

छत्तीसगढ़ 2025 : माह-दर-माह टाइमलाइन

जनवरी 2025

- साल की शुरुआत नक्सल हिंसा के साथ
- बस्तर संभाग के बीजापुर-दंतेवाड़ा क्षेत्र में मुठभेड़
- कई जवान शहीद ? सुरक्षा नीति पर बड़ा दबाव
- राज्य सरकार ने 'नक्सल उन्मूलन निर्णायक चरण' की घोषणा की

फरवरी 2025

- नगर निकाय चुनाव
- भाजपा को ऐतिहासिक बढ़त
- कांग्रेस को शहरी इलाकों में बड़ा झटका
- राजनीति में संदेश साफ़ः शहरी मतदाता सरकार के साथ।

मार्च 2025

- धान खरीदी अपने चरम पर
- रिकॉर्ड मात्रा में खरीदी, किसानों को समय पर भुगतान
- लेकिनः टोकन,लिमिट, बारदाना जैसे मुद्दों पर जमीनी नाराजगी भी।

अप्रैल 2025

- औद्योगिक निवेश का दौर
- स्टील, पावर, लॉजिस्टिक्स और एमएसएमई सेक्टर में बड़े प्रस्ताव
- रोजगार सृजन के वादे
- सरकार ने 'निवेश-अनुकूल छत्तीसगढ़' की ब्रांडिंग तेज की।

मई 2025

- प्रशासनिक फैसलों पर बहस
- मंत्रियों से सलामी गार्ड हटाने का निर्णय
- समर्थक बोलेः औपनिवेशिक परंपरा से मुक्ति
- आलोचक बोलेः प्रतीकात्मक राजनीति

जून 2025

- अबूझमाड़ और सुदूर वनांचल में सड़क व संचार विस्तार
- कई सालों से कटे इलाकों में पहली बार मोबाइल नेटवर्क
- इसे नक्सल विरोधी रणनीति का 'सबसे मजबूत हथियार' माना गया।

जुलाई 2025

- शिक्षा और डिजिटल असमानता उजागर
- वनांचल के छात्र नेटवर्क के लिए पहाड़ों पर चढ़ते दिखे
- 'डिजिटल इंडिया' बनाम 'डिजिटल हकीकत' पर बहस

अगस्त 2025

- स्वतंत्रता दिवस संदेश में विकास + सुरक्षा का संतुलन
- सरकार ने दावा कियाः 'नक्सलवाद अंतिम सांसों में '
- विपक्ष ने सवाल उठाएः 'जमीनी सच अलग है

सितंबर 2025

- भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामले सामने
- बैंकिंग, शिक्षा, पंचायत और भर्ती से जुड़े विवाद
- एसीबी की कार्रवाई
- प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल

अक्टूबर 2025

- आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं की समीक्षा
- स्वास्थ्य, पोषण, आवास योजनाओं की प्रगति
- काग़ज बनाम जमीन की खाई फिर सामने

नवंबर 2025

- राजनीतिक बयानबाजी तेज
- विपक्ष नेतृत्व संकट से जूझता दिखा
- सवाल उठाः 'क्या छत्तीसगढ़ में विपक्ष सिर्फ एक चेहरे तक सिमट गया है? '

दिसंबर 2025 साल का लेखा-जोखा

सरकार...

- निवेश
- सड़क
- सुरक्षा को उपलब्धि बताती रही

जनता...

- रोजगार
- महंगाई
- सेवा की गुणवत्ता पर जवाब मांगती रही...

रायपुर-ग्रेडः ए

- योजनाओं की तेज फाइल मूवमेंट
- मॉनिटरिंग मजबूत
- लेकिन आम नागरिक तक पहुँच में दूरी
- स्थितिः राजधानी का प्रशासन तेज, संवेदनशील कम
- कुल राज्य औसत ग्रेडः बी- प्रशासन चला, पर हर जगह समान नहीं चला।

जिला-वार प्रशासनिक रिपोर्ट कार्ड (2025)

ग्रेडिंग आधारः

- सेवा वितरण
- प्रशासनिक स्थिरता
- भ्रष्टाचार नियंत्रण
- फील्ड उपस्थिति
- जन-संतोष

बीजापुर—ग्रेड :D

- प्रशासन पूरी तरह सुरक्षा-केंद्रित
- विकास योजनाएँ धीमी
- अधिकारी निर्णय से ज़्यादा अनुमति पर निर्भर
- स्थितिः प्रशासन मौजूद, पर नागरिक अनुपस्थित

सुकमा-ग्रेड : D

- सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सबसे कमजोर
- फाइल आगे, फील्ड पीछे
- शिकायतों का समाधान न्यूनतम
- स्थितिः राज्य का सबसे उपेक्षित प्रशासनिक जिला

नारायणपुर-ग्रेड : C

- नेटवर्क व सड़क में सुधार
- लेकिन योजनाओं की निगरानी कमजोर
- अधिकारी बदलते रहे
- स्थितिः संभावनाएँ हैं, पर पकड़ नहीं

दंतेवाड़ा-ग्रेड :C

- शिक्षा-स्वास्थ्य में औसत प्रदर्शन
- सुरक्षा और प्रशासन में तालमेल बेहतर
- लेकिन भ्रष्टाचार शिकायतें बनी रहीं
- नियंत्रण है, भरोसा नहीं

सरगुजा-ग्रेड : B-

- आदिवासी योजनाओं का असर दिखा
- डिजिटल सेवाओं में असमानता
- जिला प्रशासन सक्रिय, पर संसाधन सीमित
- स्थितिः ईमानदार कोशिश, अधूरा परिणाम

कोरिया-ग्रेड : B

- प्रशासनिक सक्रियता अच्छी
- लेकिन शिक्षा, बैंकिंग व राजस्व में विवाद
- शिकायतों पर कार्रवाई देर से
- स्थितिः काम हुआ, विश्वास डगमगाया

बिलासपुर-ग्रेड : B+

- न्यायिक व प्रशासनिक समन्वय बेहतर
- शहरी सेवाओं में सुधार
- ग्रामीण इलाकों में धीमापन
- स्थितिः संतुलित, पर असमान

प्रशासन को आत्ममंथन करना होगा, वरना 2026 असंतोष का साल बनेगा

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025 के प्रशासनिक रिपोर्ट कार्ड ने शासन-प्रणाली की चिंताजनक तस्वीर सामने रखी है,जिला-वार मूल्यांकन में जहाँ कुछ शहरी जिलों को ए-बीग्रेड मिला, वहीं नक्सल व आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सी और डी ग्रेड का प्रभुत्व यह दर्शाता है कि प्रशासनिक विकास समान और संतुलित नहीं रहा, यह रिपोर्ट स्पष्ट संकेत देती है कि प्रशासन फाइल-केंद्रित रहा, नागरिक-केंद्रित नहीं, डिजिटल सेवाएँ जमीन पर विफल रहीं, शिकायत निवारण प्रणाली भरोसा नहीं जगा सकी, अधिकारियों की स्थिरता और जवाबदेही दोनों कमजोर पड़ीं यदि 2026 में भी यही कार्यशैली जारी रही, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि जन-असंतोष का संस्थागत कारण बन सकती है, प्रेस के माध्यम से शासन-प्रशासन को यह चेतावनी दी जाती है कि अब भी समय है आदेशों से बाहर निकलकर जमीन पर प्रशासन दिखाने का, अन्यथा, 2026 में जनता की चुप्पी 2028 में प्रश्न बनकर लौटेगी।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा साईं ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2023-2025-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)